लखनऊ

बुधवार, 8 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 224

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"जो सुबह अपने लक्ष्य को याद कर लेते हैं, उनका पूरा दिन सफलता के इर्द-गिर्द घूमता है।"

TODAY WEATHER

DAY 28° Hi

NIGHT 17° Low

संक्षेप

महाकुंभ वाले IIT वाले बाबा अभय सिंह ने कर ली शादी

प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में सुर्खियां बटोरने के बाद आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए झज्जर के अभय ने शादी कर ली है। शादी के बाद वे अपनी पत्नी प्रितिका के साथ अपने पैतृक शहर झज्जर पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बताया जा रहा है कि दंपति बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए झज्जर आए थे। इस दौरान अभय ने तहसील परिसर में स्थित अपने वकील पिता कर्ण सिंह ग्रेवाल के चैंबर में कुछ समय बिताया और मीडिया से भी बातचीत की। आईटीआई बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए आगंतुक कक्ष के अंदर कतार में खड़े थे, वहीं कई स्थानीय लोगों ने अभय के साथ फिर से जुड़ने और पुरानी यादों को ताजा करने का मौका उठाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी प्रीतिका बेंगलुरु की रहने वाली हैं और दोनों एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। अपने माता-पिता से मिलने के बारे में पूछे जाने पर अभय ने कहा कि वे उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कभी-कभी बड़े पारिवारिक दायित्वों के कारण छोटे परिवार से दूर रहना पड़ता है। भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्माण पर काम चल रहा है, जहां ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अकादमिक शिक्षण के साथ-साथ आध्यात्मिक साधना और ध्यान से संबंधित ज्ञान पर भी काम किया जाएगा।

एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा, जुलाई 2027 तक था कार्यकाल

नई दिल्ली। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एयरलाइन लगातार वित्तीय दबाव झेल रही है और हाल के वर्षों में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नियामकीय जांच का सामना कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विल्सन के इस्तीफे के बाद एयर इंडिया का बोर्ड नए सीईओ की तलाश में तेजी लाएगा। इसे एयरलाइन के पुनर्गठन (टर्नअराउंड) की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड में जन्मे कैम्पबेल विल्सन को वर्ष 2022 में सिंगापुर एयरलाइंस से एयर इंडिया लाया गया था। टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद उन्हें कंपनी के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक निर्धारित था, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही पद छोड़ने का निर्णय लिया। फिलहाल, वह छह महीने के नोटिस पीरियड के दौरान कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। पिछले वर्ष जून में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान के टेकऑफ के तुरंत बाद हुए विमान हादसे के बाद से कंपनी और उसके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। इस दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया वर्तमान में कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें विमानों की डिलीवरी में देरी, सुरक्षा मानकों को लेकर उठते सवाल और लगातार हो रहा वित्तीय नुकसान शामिल हैं। नियामक संस्थाओं ने भी एयरलाइन की परिचालन प्रक्रियाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में, नए नेतृत्व की नियुक्ति को एयर इंडिया के भविष्य और उसके सुधार प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

असम रैली में गरजे अमित शाह, बोले- राहुल बाबा सुन लें, घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम के पथारकंडी में एक रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य को घुसपैठियों से प्रभावित क्षेत्र नहीं बनने देगी। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं आज यहीं से यह घोषणा करता हूं, और राहुल बाबा, इसे ध्यान से सुनिए, हम असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि भाजपा ने घुसपैठियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को चुनिए। हमने घुसपैठियों की पहचान कर ली है। अब समय आ गया है कि उन्हें एक-एक करके बाहर निकाला जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें सत्ता में आती हैं तो घुसपैठ बंद हो जाएगी। पार्टी के सांस्कृतिक एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करते हुए शाह ने कहा कि केवल भाजपा में ही करीमगंज का नाम बदलकर 'श्रीभूमि' करने का संकल्प है, साथ ही उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि वह राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए घुसपैठियों पर निर्भर है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने क्षेत्रीय भावनाओं को समझने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जिनकी जड़ें इटली में हैं, वे भला 'श्रीभूमि' का महत्व कैसे समझ सकते हैं? उन्होंने केंद्र सरकार की पहलों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का श्रेय दिया। शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का बचाव करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया।

शाह ने आरोप लगाया कि जब भी हम सीएए की बात करते हैं, कांग्रेस इसका विरोध करती है। एक साजिश के तहत, उन्होंने इस क्षेत्र को घुसपैठियों का गढ़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने 1950 के आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम को निरस्त कर दिया और बाद में घुसपैठियों को पनाह देने के लिए 1983 में आईएमडीटी अधिनियम लागू किया। उन्होंने आगे कहा कि असम और आसपास के राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें घुसपैठ रोकने के लिए मिलकर काम करेंगी। जैसे ही असम, बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा-एनडीए सरकारें बनेंगी, घुसपैठ बंद हो जाएगी। हम व्यवस्थित रूप से हर एक घुसपैठिए की पहचान करके उसे निष्कासित करेंगे।

क्या मर्यादा भूली कांग्रेस, गुजरात का अपमान क्यों? खरगे के बयान पर किया पलटवार: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खरगे के कथित गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताने वाले बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने इस टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया और कांग्रेस अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह मर्यादा भूल चुका है? प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या किसी राज्य के लोगों को इस तरह संबोधित करना उचित है।

योगी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला : अंबेडकर स्मारकों का होगा सौंदर्यीकरण, शिक्षामित्र की वेतन में बंपर बढ़ोतरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अंबेडकर जयंती से पहले, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने राज्य भर में सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाने वाले स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल को मंजूरी दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सरकार ने बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमाओं को सजावटी छतरियों, चारदीवारी और व्यापक सौंदर्यीकरण उपायों के साथ उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इन स्मारकों के सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना और साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक व्यापक विकास योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारक स्थलों का जीर्णोद्धार करेगी। इसके लिए कुल 403 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना केवल अंबेडकर तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसमें रविदास, कबीर, ज्योतिराव फुले और वाल्मीकि जैसे प्रमुख समाज सुधारकों की प्रतिमाओं और स्मारकों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सामाजिक समानता और सुधार में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके। पहले चरण में, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित प्रतिमाओं के व्यापक सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचा, रखरखाव और दृश्य सौंदर्य सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक प्रशिक्षकों के मासिक मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

जैसी सबकी अलग प्रथा, वैसी सबरीमाला की भी : एस जी तुषार मेहता

'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी ...', सबरीमाला मंदिर मामले में एसजी मेहता ने दी दमदार दलील

नई दिल्ली, एजेंसी। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी रहे या नहीं, इसे लेकर मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू, इस्लाम और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर चर्चा हुई। कोर्ट धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं का 22 अप्रैल तक निपटारा करने के लिए सुनवाई कर रहा है। ये याचिकाएं अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं। इस सुनवाई में मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना और दूसरे धर्म में शादी करने वाली पारसी महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार मिले या नहीं जैसे मुद्दों पर भी फैसला करेगा। केंद्र ने हलफनामे में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए रखने की अपील की है। केंद्र का कहना है कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, यानी जीवनभर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। केंद्र ने कहा कि अगर महिलाओं को प्रवेश दिया गया तो मंदिर की पारंपरिक पूजा पद्धित बदल जाएगी, जिसका संविधान में संरक्षित धार्मिक विविधता पर असर पड़ सकता है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला मंदिर मामले में जस्टिस तरुण गोगोई ने आदेश लिखा था और आदि शैव फैसला भी उन्होंने ही लिखा, जिसमें श्रीर मठ से लेकर आज तक के कानून का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि श्रीर मठ से लेकर सबरीमाला तक के मामलों में कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। एक तो संविधान सभा में हुई बहसों का। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत में धर्मों की विशालता और उनका व्यापक दायरा है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर उप-संप्रदाय हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। ऐसे ही इस्लाम में भी उप-संप्रदाय हैं। हालांकि इस्लाम में एक ही पवित्र किताब है और एक संस्थापक हैं, फिर भी इस धर्म में आंतरिक विविधताएं हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जज साहब आप धर्मशास्त्र से जुड़े पहलुओं की जांच नहीं कर रह हैं, लेकिन कोर्ट को इस बात पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि इस्लाम का मतलब सिर्फ एक तरह का इस्लाम नहीं और न ही हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ एक तरह का हिंदू धर्म है। उन्होंने कहा कि धर्म और धार्मिक मामलों की व्याख्या करते वक्त कोर्ट को इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि हमने संविधान में अमेरिकी संविधान से कुछ स्वतंत्रताएं ली हैं, लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 विशेष रूप से भारत के संदर्भ में तैयार किए गए है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में दशम दशनामी संप्रदाय का ही हिस्सा है, जिसमें हर किसी का एक अलग नाम होता है। आप किसी संत के नाम से ही पहचान सकते हैं कि वह गिरी, तीर्थ, भारती या किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े हैं। हर किसी का तिलक अलग होता है, उनका नमस्ते करने का तरीका अलग होता है, जिससे उन्हें पहचाना जाता है कि वह दशनाम में किस कैटेगरी से हैं।

सीईसी ज्ञानेश कुमार को राहत! संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने ही विचार-विमर्श के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए दायर महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सदस्यों को सूचित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5), अनुच्छेद 124(4), मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 12 मार्च, 2026 का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुमार को पद से हटाने की मांग की गई थी। सभी प्रासंगिक पहलुओं और संबंधित मुद्दों का सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के बाद, राज्यसभा के अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकसभा सचिवालय ने कहा किभारत के संविधान (अनुच्छेद 324(5) व 124(4)) और मुख्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 12 मार्च, 2026 के एक प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी। सचिवालय ने कहा, प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार-विमर्श करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने भी विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया।

भर्ती पर सवाल उठाने पर एक्टिविस्ट के खिलाफ एफआईआर, संस्था पर उठे सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को अक्सर घटिया या मिलावटी खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट सामने आने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि, देश की खाद्य सुरक्षा संबंधी नोडल संस्था इस बार एक बिल्कुल अलग विवाद में घिरी है। पांच शीर्ष अधिकारियों की भर्ती पर सवाल उठाने वाले कार्यकर्ताओं को आपराधिक मामले में फंसाकर चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। पांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्यकर्ताओं ने तथ्यों का पता लगाने के लिए दिसंबर 2024 में गठित एक आंतरिक समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया है। एफआईआर एफएसएसएआई के एक अधिकारी की शिकायत पर आधारित थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने ऐसी कोई शिकायत मांगी थी या नहीं।

मुख्यमंत्री हिमंता की पत्नी पर टिप्पणी पड़ी भारी, पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर, दिल्ली पहुंची असम पुलिस

नई दिल्ली, एजेंसी। असम पुलिस ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। यह दौरा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान द्वारा उनके खिलाफ पासपोर्ट धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के एक दिन बाद हुआ। इस दौरे के दौरान दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन क्षेत्र में असम पुलिस दल की सहायता की। इससे पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह की झूठी जानकारी के आधार पर उनकी पत्नी के कई पासपोर्ट होने और दुबई में संपत्तियां होने का आरोप गढ़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान असम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने शर्मा की पत्नी की या उनके परिवार की दुबई में संपत्ति होने, अमेरिका के व्योमिंग में कंपनियां होने या मुखौटा कंपनियों में संपत्ति होने का आरोप लगाया था। इसके एक दिन बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा कि ये आरोप चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए लगाए गए हैं, जो कानून के तहत दंडनीय है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनकी पत्नी के खिलाफ जो दस्तावेज इस्तेमाल किए, वे ''पाकिस्तानीज इन अजमान'' नाम के एक सोशल मीडिया समूह से लिए गए थे और उनकी तस्वीर को किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के खोए हुए पासपोर्ट पर छेड़छाड़ कर लगाया गया था। सरमा ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं, मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित हैं और राज्य में चुनावी माहौल को खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली। यह कोई साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का पहलू स्पष्ट हो गया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच करते समय इसे ध्यान में रखेंगी।

पवन खेड़ा के घर पुलिस भेजने पर भड़के जयराम रमेश, बोले- मुख्यमंत्री हिमंता परेशान और डरे हुए हैं

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें परेशान, हताश और डरा हुआ बताया। यह घटना तब हुई जब असम पुलिस की एक टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। पुलिस की यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल पासपोर्ट विवाद से संबंधित है, जो मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की एफआईआर के बाद सामने आया है। एक्स से बात करते हुए रमेश ने निजामुद्दीन पूर्व स्थित खेड़ा के घर के बाहर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की निंदा की और इसे 'चुड़ैल का शिकार' और 'दंभिक' द्वारा राज्य मशीनरी का उपयोग करके विपक्ष की उन आवाजों को दबाने का प्रयास बताया जो कथित कुकर्मों को उजागर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और भयभीत हैं। यह कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जिसमें एक तानाशाह विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी असम पुलिस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री सरमा से आग्रह किया कि वे धमकियों और अपशब्दों का सहारा लेने के बजाय खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों का समाधान करें।

'महिला आरक्षण कानून से बढ़ेगा नेतृत्व', पीएम मोदी ने दोहराया- 2029 से पहले लागू करने का प्रयास

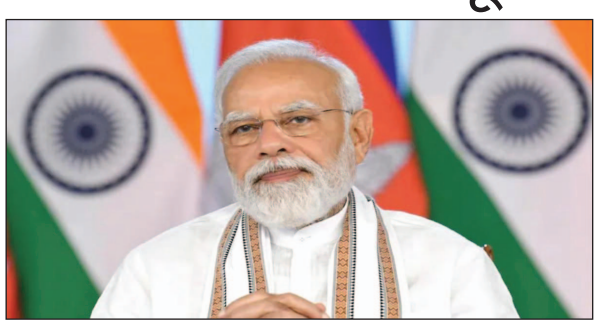

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने हर स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए भारत महिला-नेतृत्व वाले शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रतिनिधित्व का वास्तविक प्रभाव में बदलना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के उस लेख पर की, जिसमें महिलाओं की विधायी भागीदारी बढ़ाने और समावेशी शासन की जरूरत पर जोर दिया गया है। एक्स पर मोदी ने कहा कि प्रतिनिधित्व का मतलब वास्तविक प्रभाव होना चाहिए। हमारी सरकार ने हर रूप में नारी शक्ति को प्राथमिकता दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए भारत महिला-नेतृत्व वाले शासन की ओर बढ़ रहा है, जो विकसित भारत का एक अहम स्तंभ है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण कानून कहा जाता है, 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह कानून संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है और इसके प्रभावी होने के लिए परिसीमन प्रक्रिया का पूरा होना जरूरी है। हालांकि, सरकार इस कानून को 2029 से पहले लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र को तीन दिन 16 से 18 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है, ताकि कानून में आवश्यक संशोधन कर इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, अगर सरकार परिसीमन प्रक्रिया से पहले इस कानून को लागू करना चाहती है, तो इसके लिए संविधान में एक और संशोधन करना होगा। माना जा रहा है कि संसद के विस्तारित सत्र में इस दिशा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर खुले मन से समर्थन दें और राजनीतिक गणनाओं से ऊपर उठें। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की माताओं और बहनों के विश्वास को जीतने का अवसर है, और सभी दलों को इसमें सहभागी बनना चाहिए।

अधिवक्ता समीर हत्याकांड: फांसी की सजा का फैसला सुन फीके पड़े चेहरे, 52 पेज में जज ने लिखी ये बात

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी (28) की सात साल पहले अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई। वहीं, अदालत ने साक्ष्य खुदबुर्द करने में दिनेश को सात साल की कैद की सजा सुनाई। सभी पर कुल 15 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि हमला केवल अधिवक्ताओं पर ही

नहीं, बल्कि एक संस्था पर हमले के समान है। एडवोकेट बार को सीधे चुनौती देने जैसा है। अधिवक्ता की हत्या न हो, इसलिए मृत्युदंड देना चाहिए। अधिवक्ता समीर सैफी ने 15 अक्तूबर 2019 को अपने चैंबर का उद्घाटन किया था। इसके बाद शाम को संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे। पिता अजहर ने गुमशुदगी दर्ज कराई। 19 अक्तूबर को भोपा थाना क्षेत्र के सीकरी से उनका शव बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अधिवक्ता के दोस्त सिंगोल अल्वी से पूछताछ की तो हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने अल्वी, उसके ड्राइवर सोनू उर्फ रिजवान, नौकर शालू उर्फ अरबाज एवं दिनेश को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि अपहरण के बाद अधिवक्ता को भोपा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास ले गए। रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों मोबाइल कूकड़ा रोड स्थित नाले में फेंक दिए। इसके बाद शव को बोरे में बंद कर सीकरी फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा किया था। मुर्गी फार्म के 40 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। वादी के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि छह गवाह पेश किए गए। चार अप्रैल को आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ था।

इन्हें सुनाई गई फांसी की सजा

शहर के बकरा मार्केट निवासी सोनू उर्फ रिजवान, सिंगोल अल्वी, शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई गई। भोपा के सीकरी गांव निवासी दिनेश को सात साल कारावास की सजा हुई। समीर सैफी हत्याकांड में अदालत ने शैलेंद्र जसवंत भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, माछी सिंह, बच्चन सिंह, निर्मल सिंह, धनंजय चटर्जी, शंकर लाल, त्रिवेणी बेन, मुकेश और पुरुषोत्तम केस की रुलिंग भी लिखी गई है। इनके हवाले से पूरे प्रकरण को स्पष्ट करने की कोशिश की गई।

फैसला सुनते ही फीके पड़ गए चेहरे

अदालत का फैसला आते ही दोषियों के चेहरे फीके पड़ गए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दोषियों को हवालात ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में जगह-जगह परिजन भी खड़े हुए नजर आए। दोषियों के परिवार की महिलाएं भी यहां पर काफी संख्या में पहुंची थी। मुजफ्फरनगर के लद्दावाला के समीर सैफी (28) की हत्या के मामले में अदालत ने करीब सात साल बाद फांसी की सजा का फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने अपने 52 पेजों के फैसले में रिश्तों में हत्या, मानवीय पहलू, अधिवक्ताओं के अधिकार और विवेचना की स्थिति पर टिप्पणी की है। एक कविता भी लिखी जिसमें लिखा है कि और मरकर भी वकील की आवाज इंसाफ ही रचती है...। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अधिवक्ता बंधुओं पर हमला केवल अधिवक्ताओं पर ही हमला नहीं है, बल्कि यह एक संस्था पर हमले के समान है। उस संस्था अर्थात् एडवोकेट बार को सीधे चुनौती देने जैसा है।

दोस्त की हत्या... खत्म करती है भरोसे की नींव

सिंगोल अल्वी (मुख्य अभियुक्त) को गवाह नंबर एक ने मृतक एडवोकेट समीर का दोस्त, विश्वासपात्र एवं व्यवसायिक साथी बताया है। प्रकरण में एक दोस्त की सुनियोजित साजिश के तहत लालच में निर्मम हत्या की गई है। दोस्त की हत्या करना सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवीय संबंधों के टूटने का सबसे निचला स्तर है। दोस्ती को सबसे पवित्र और चुने हुए रिश्ते के रूप में देखा जाता है। जब कोई दोस्त अपने दोस्त को मारता है, तो वह केवल शरीर को नष्ट नहीं करता है बल्कि भरोसे की नींव को खत्म कर देता है। दोस्त की हत्या यह सिद्ध करती है कि मानव स्वभाव में प्रेम व विश्वास के साथ-साथ अत्यंत अंधेरा और हिंसक पक्ष भी हो सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया तर्क

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप कुमार की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सिद्धदोष सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान व शालू उर्फ अरबाज ने मृतक समीर की हत्या षड्यंत्र के तहत एक राय होकर की। निर्मम तरीके से रस्सी से गला घोंटा गया। सिद्धदोष दिनेश की सहायता से साक्ष्य मिटाए जाने के आशय से शव को मिट्टी में दबा दिया। दोषियों को मृत्युदंड से दंडित किया जाए, जिससे समाज में सही संदेश जाए।

हाईटेक 'एन-नेक्स्ट' डाकघर का उद्घाटन, युवाओं को जोड़ेगा नई तकनीक से

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। केंद्रीय संचार मंत्री माधवराव सिंधिया की पहल पर भारतीय डाक सेवा को 21वीं सदी के अनुरूप आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। 'एन-नेक्स्ट' योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित कमला नेहरू तकनीकी संस्थान के उपडाकघर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक डाकघर के रूप में विकसित किया गया है।

इस नवनिर्मित डाकघर का उद्घाटन प्रयागराज रीजन के पोस्टमास्टर जनरल राजीव उमराव ने किया और इसे जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल डाक विभाग के आधुनिकीकरण का प्रतीक है, बल्कि युवाओं को डाक विभाग की योजनाओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने डाक

अधीक्षक राजेश कुमार तिवारी की मेहनत और सरकार की मंशा की सराहना करते हुए कहा कि सुल्तानपुर ने एक बार फिर डाक विभाग को नई दिशा देने का कार्य किया है। यह हाईटेक डाकघर आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं के साथ ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम में सहायक अधीक्षक ए.के. त्रिपाठी, पवन मिश्रा, वरिष्ठ निरीक्षक दीपक मौर्य, कादीपुर से पवन त्रिपाठी, विकास सिंह, स्टेनो के.के. मिश्रा, आदर्श वर्मा, दीक्षा, आकांक्षा, शिवांगी, एएसके चौबे (पोस्टमास्टर) सहित संस्थान के प्रोफेसर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस पहल से क्षेत्र में डाक सेवाओं को नई गति मिलेगी और युवा वर्ग को आधुनिक तकनीक के माध्यम से डाक विभाग से जोड़ने में मदद मिलेगी।

मेरठ के डेविल के क्या थे मंसूबे... पिछले डेढ़ साल के रेल हादसों की जांच शुरू, आतंकी कनेक्शन पर दुबई से क्या बोला आकिब?

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। यूपी एटीएस ने पिछले सप्ताह चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन आतंकियों को मेरठ निवासी साकिब ने आतंकी संगठनों के इशारे पर रेल दुर्घटनाएं कराने के लिए तैयार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर इनसे रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर बड़ी रेल दुर्घटना कराने का लक्ष्य देते थे।

एटीएस के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों के गिरोह में 10 से ज्यादा युवक शामिल थे। इन्हें हथियार चलाने के साथ-साथ रेल दुर्घटना को अंजाम देने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। पाकिस्तानी हैंडलर वीडियो भेजकर ट्रेनिंग देते थे। उसी ट्रेनिंग के आधार पर कुछ आतंकियों ने रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर बड़ी दुर्घटना करने

की कोशिश भी की थी।

रेल हादसों की जांच शुरू

इस खुलासे के बाद एटीएस ने पिछले डेढ़ वर्ष में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर या अन्य वस्तुएं रखे जाने के सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल लोकेशन और टावर डेटा निकाल लिया है। अब संबंधित स्थानों पर इन आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि की जा रही है।

मेरठ और गौतमबुद्ध नगर से गिरफ्तार किए गए थे

आतंकी

एटीएस ने पिछले शुक्रवार को मेरठ निवासी साकिब और अरबाब, गौतमबुद्ध नगर निवासी विकास गहलावत और लोकेश पंडित को गिरफ्तार किया था। ये सभी आतंकी संगठनों के लिए रेलवे स्टेशनों, सरकारी संस्थानों और नेताओं की रेकी कर सूचनाएं भेजने के आरोप में पकड़े गए। कोर्ट ने एटीएस को इन चारों का 5 दिन का रिमांड दे दिया है।

असलहों का शौकीन था साकिब

पूछताछ में अरबाब, विकास और लोकेश ने बताया कि साकिब को असलहों का शौक था। आतंकी संगठन क्यूआर कोड के जरिए पैसे भेजते थे, जिनसे वह हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा था। सूत्रों का कहना है कि यह गिरोह रेलवे को निशाना बनाने की बड़ी साजिश रच रहा था।

क्या बोला आकिब?

दुबई से सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो बयान में आकिब ने सफाई देते हुए कहा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं सच्चा देशभक्त हूं। आकिब ने आगे कहा, जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ करो। किसी बेगुनाह को न फंसाया जाए। बीते साल साकिब उर्फ डेविल के साथ आकिब का वीडियो कॉल वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर के साथ AK-47 और हैंड ग्रेनेड दिखाई दे रहा था। ATS की पूछताछ में साकिब के ISI हैंडलर से कनेक्शन की कड़ी आकिब तक भी जुड़ी बताई गई थी। कार्रवाई शुरू होने के बाद अब दुबई में बैठे आकिब ने खुद सामने आकर वीडियो जारी कर सफाई दी है।

सेंट्रल मार्केट पर सियासत तेज, अतुल प्रधान बोले- सांसद गोविल को बुलाओ, असली फिल्म तो यहां चल रही है

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने व्यापारियों के समर्थन में बयान देते हुए सांसद को हस्तक्षेप करने की सलाह दी है।

अतुल प्रधान ने कहा कि सांसद अरुण गोविल को आगे आकर व्यापारियों की समस्या सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद को बुलाया जाए, अगर वह मुंबई में भी हों तो विमान पकड़कर मेरठ आएं। उन पर भगवान श्रीराम का तमगा है, इसलिए उनकी बात को लोग ज्यादा सुनेंगे।

विधायक ने कहा कि वह खुद को एक साधारण व्यक्ति बताते हुए व्यापारियों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सांसद की जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि उनके नेता अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में कहा था कि सांसद अरुण गोविल को

सदन में आगे बैठाया जाए।

व्यापारियों से की एकजुट रहने की अपील

अतुल प्रधान ने व्यापारियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि आपस में बंटने के बजाय एकजुट रहकर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि जो सरकार गलत थी उसे जनता ने हटा दिया, लेकिन अब अपनी बात रखने पर भी भाजपा का विरोध माना जाता है। उत्तेजित लहजे में उन्होंने कहा कि अगर विरोध होता है तो होने दें, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों न हो। उन्होंने कहा कि फिल्मों का प्रचार हो रहा है, जबकि असली फिल्म तो सेंट्रल मार्केट में चल रही है, जहां व्यापारी अपनी रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं।

भाजपा पर साधा निशाना

विधायक ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार आने पर नियमों में बदलाव कर व्यापारियों को राहत दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सदन में यह बात भी रखी कि यहां के व्यापारी भाजपा के समर्थक रहे हैं, ऐसे में सरकार को उन्हें राहत देनी चाहिए। अतुल प्रधान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को घमंड चढ़ गया है और भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। उन्होंने कहा कि मेरठ में भाजपा का पश्चिम क्षेत्र का बड़ा कार्यालय है और यहां प्रधानमंत्री की रैली भी होती है, ऐसे में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए।

प्रवेशोत्सव व मेधावी सम्मान समारोह में छात्रों का हुआ उत्साहवर्धन

सुल्तानपुर। उच्च प्राथमिक विद्यालय हसनपुर द्वितीय में प्रवेशोत्सव एवं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रामतीर्थ वर्मा ने मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल एवं पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता किसी अमृत से कम नहीं है, लेकिन अभिभावकों को भी इन विद्यालयों की गुणवत्ता को समझने और उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अध्यक्षता हसनपुर के पूर्व प्रधान हनुमत विद्यामंदिर के प्रबंधक इन्द्र नारायण तिवारी ने की। उन्होंने विद्यालय के स्टाफ एवं छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही हनुमत विद्यामंदिर के प्रबंधक इन्द्र नारायण तिवारी ने छात्रा को अपने विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देने का आश्वासन भी दिया।

बरेली में फिर चला बुलडोजर, मजार के समीप कई अवैध दुकानें ध्वस्त, कार्रवाई से मची खलबली

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। बरेली में नगर निगम ने अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने मंगलवार को दोपहर करीब एक बजे कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप के सामने अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इन दुकानों पर नगर निगम की ओर से लाल निशान लगाए थे, लेकिन दुकानदारों ने लाल निशान मिटा दिए थे। दो बुलडोजरों से अवैध दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिससे मौके पर खलबली मच गई।

50 से 55 अतिक्रमण किए गए चिन्हित

सीएम ग्रिड योजना (मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम) के दूसरे चरण के तहत 50 से 55 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत कोहाड़ापीर से कुदेशिया मार्ग और धर्मकांटे से कोहाड़ापीर तक अभियान चलाया जाना है। मंगलवार को कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप के सामने मजार के समीप स्थित अवैध दुकानों के ध्वस्तीकरण से कार्रवाई की शुरुआत की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।

भवन मालिकों ने मिटा दिए थे लाल निशान

नगर निगम के एक्सईएन राजीव कुमार राठी के मुताबिक नगर निगम को सूचना मिली थी कि कई भवन मालिकों ने अपने प्रतिष्ठानों से लाल निशान हटा दिए हैं। निगम ने इस पर संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में राहत नहीं दी जाएगी। सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। निगम में अभियान से पहले पुलिस व प्रशासन का सहयोग मांगा है, जिससे कार्रवाई के दौरान बाधा न आए।

एक्सईएन ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध कब्जों को हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने या सरकारी निशान से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी को मारने को नैनीताल से रामपुर तक कई बार बदलीं शातिराना चालें, महिला सिपाही और बेटे के कत्ल की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर. यूपी के रामपुर जिले में महिला सिपाही लता और दो साल के बेटे लड्डू को मौत के घाट उतारने के लिए पति दान सिंह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने शातिराना पटकथा तैयार की थी। बचने की कोई गुंजाइश न रहे इसके लिए नैनीताल से रामपुर तक के सफर में उसने कई बार अपनी साजिश बदली। हादसे से कार में आग के कारण मौत की बात कहने वाले दान सिंह का कुबूलनामा सामने आने के बाद पुलिस भी मान रही है कि पूरी साजिश में आरोपी का रवैया पेशेवर अपराधियों जैसा है। साजिश की शुरुआत नई कार के बहाने परिवार को नैनीताल घुमाने की कहानी से हुई। वहां से लौटते समय जैसे-जैसे कार आगे बढ़ी, वैसे-वैसे साजिश की स्क्रिप्ट के पेज भी आगे बढ़ते गए। बाजपुर में कार रोककर पत्नी लता और

बेटे लड्डू को नशे की गोलियां मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाया। उनके बेहोशी में आने पर कार को पास से गुजरते डंपर से छुआते हुए निकाला, जिससे दुर्घटना का दृश्य बन जाए।

साजिश की किताब के अगले हिस्से में दान सिंह के पहले से तय हुए दो साथी प्रदीप और सलमान पेट्रोल लेकर एक अन्य कार में मौजूद थे। दान सिंह ने कार की डंपर से टक्कर बताने के साथ कार सवार साथियों का लाया पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दान सिंह की कार आग में घिरी तो लपटों में घिरा लड्डू तो हमेशा के लिए सो गया लेकिन तपिश से लता को चेतना आई तो वह कार से निकल बाहर भागी। नशे का असर होने से लड़खड़ाती लता सड़क किनारे गड्ढे में गिरी, जिसमें पानी भरा था। यहां मौत की साजिश का एक और अध्याय शुरू हुआ। उसी पानी में मुंह डुबोकर लता को मारने का प्रयास किया। इस बीच कार की आग देख राहगीर रुकने लगे तो फौरन प्लान बदल दिया। साथियों की कार से लता को इलाज के बहाने ले भागा और कार में पहले से रखा हथौड़ा सिर में मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

बाद में अस्पताल में पछाड़ खाकर रोने-चीखने का ऐसा रूप धरा कि उस वक्त हर कोई उसे बेचारा मान बैठा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दान सिंह के बयानों में जैसे-जैसे साजिश-दर-साजिश के राज सामने आए तो अंदाजा लगा कि वह कितना बड़ा शातिर है। उस समेत साजिश में शामिल उसके दो साथी गिरफ्तार कर लिए हैं। अन्य दो की तलाश की जा रही है।

यूपी के रामपुर जिले में महिला सिपाही और उसके मासूम बेटे की मौत हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। कार में ही सवार महिला सिपाही के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मार डाला था। आरोपी ने पत्नी को मारने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने नैनीताल से आते समय बाजपुर में ही पत्नी और बेटे को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी थीं। इसके बाद काशीपुर रोड पर कार में एक डंपर से हल्की टक्कर लगाई और दो दोस्तों से पेट्रोल मंगवाकर कार में आग लगा दी थी। गंज कोतवाली इलाके में काशीपुर गांव के पास 25 फरवरी की रात हुई इस घटना में खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए महिला सिपाही के पति और उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो साथी भागे हुए हैं। पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे पत्नी की मौत के बाद मिलने वाली डेढ़ करोड़ रुपये की सरकारी मदद को हड़पना था।

आरोपी और लता ने की थी लव मैरिज

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि सीतापुर निवासी लता ने वर्ष 2021 में मिलक के ग्राम बेहटरा निवासी दान सिंह के साथ लव मैरिज की थी। शादी के बाद से लता सीतापुर में रहने के लिए दान सिंह पर दबाव डाल रही थी। जिस पर उसने लता और बेटे लड्डू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने अपने इस प्लान में रवि के अलावा नूरहसन, प्रदीप कुमार और अब्दुल करीम को शामिल किया।

कोल्डड्रिंक में मिला दी नींद की गोलियां

फिर प्लान के तहत दान सिंह अपनी पत्नी लता और बेटे लड्डू को लेकर नैनीताल गया। साथ में रवि भी था। वापस आते समय बाजपुर के पास दान सिंह ने कार रोकी और दो कोल्डड्रिंक लीं। दोनों में उसने नींद की गोलियां मिला दीं फिर लता और लड्डू को दे दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद दान सिंह ने जिस तरफ लता बैठी थी, वह साइड डंपर से अपनी कार टकरा दी, ताकि हादसा लगे। इसके बाद दान सिंह ने अपने साथी प्रदीप और सलमान को पेट्रोल लेकर बुलाया। दोनों ने कार पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगा दी।

कार में जल गया मासूम

इसके बाद दान सिंह व रवि कार से कूद गए। कुछ देर में ही कार जलने लगी। आग लगने के कारण लता होश में आ गई और कार से बाहर निकली तो बाहर एक पानी भरे गड्ढे में गिर गई। वहां भी दान सिंह ने उसका मुंह पानी में डुबाने की कोशिश की। इस दौरान लड्डू कार के अंदर ही जल गया। ग्रामीणों के आने और प्लान फेल होता देख दान सिंह ने फिर पैंतरा बदला, उसने एंबुलेंस से लता को ले जाने की बजाय दूसरी कार में बैठाकर वह संजीवनी अस्पताल की ओर चल दिया। रास्ते में कार में रखी हथौड़ी से दो वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

पहली पत्नी की भी सड़क हादसे में हुई थी मौत

एसपी ने बताया कि दान सिंह की लता के साथ दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी शादी शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पसतौर निवासी रजनी के साथ हुई थी। वर्ष 2015 में ग्राम रौरा कला में हुए सड़क हादसे में रजनी की मौत हो गई थी।

कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इन निर्णयों से प्रदेश में परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण, युवाओं के सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश बढ़ाने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके तहत प्रथम चरण में 54 और द्वितीय चरण में 49 बस स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इन बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होटल, भोजनालय, व्यावसायिक परिसर और बहुस्तरीय वाहन पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निजी निवेशकों को निर्धारित अवधि तक संचालन का अधिकार दिया जाएगा।गोरखपुर के खजांची चौराहा क्षेत्र में लगभग 10,012 वर्गमीटर भूमि पर अत्याधुनिक बस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे नेपाल और बिहार की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार हरदोई जनपद में शाहाबाद क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए बस स्टेशन के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसमें आधुनिक टिकट व्यवस्था, विशिष्ट अतिथि कक्ष और बड़े व्यावसायिक परिसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इस चरण में 25 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अब तक प्रदेश में लगभग 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उच्च शिक्षा और कौशल विकास में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा है।औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास नीति-2022 के अंतर्गत 10 प्रमुख कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली अनुदान और वित्तीय लाभ की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।कैबिनेट ने दशकों से उपेक्षित वनटांगिया गांवों के 5070 परिवारों को जमीन का कानूनी मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा जनपदों के इन परिवारों को अब अपनी भूमि पर अधिकार मिलेगा, जिससे वे विकास कार्यों में भागीदारी कर सकेंगे।कन्नौज और हरदोई के बीच गंगा नदी पर एक बड़े पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और कन्नौज, हरदोई तथा फर्रुखाबाद के बीच संपर्क और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसी प्रकार उन्नाव और शुक्लागंज के बीच नारायणी नदी पर नए पुल और पहुंच मार्गों के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिससे कानपुर क्षेत्र की आवाजाही सुगम होगी।यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य मार्ग-29 के लगभग 28.30 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 266.70 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुरक्षित बनेगा।शिक्षा के क्षेत्र में 'एक मंडल-एक विश्वविद्यालय' नीति के तहत उन मंडलों में नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहां अभी तक राज्य विश्वविद्यालय नहीं हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों के संचालन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए विभिन्न प्रावधानों को अद्यतन किया गया है।कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में बसे 99 विस्थापित बंगाली परिवारों के पुनर्वास को औपचारिक रूप देते हुए उनके पट्टे और किराया संबंधी नियमों को स्पष्ट किया गया है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े।

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रहीं नागरिक सूचना पट्ट, बढ़ रही आय और आत्मनिर्भरता

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के नेतृत्व व निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं प्रदेश में मनरेगा योजना के अभिसरण से नागरिक सूचना पट्ट का निर्माण कर रही हैं। मनरेगा के कार्य आरंभ होने से पूर्व सभी कार्यस्थलों पर स्थापित किए जाने वाले नागरिक सूचना पट्ट का निर्माण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं।इस कार्य से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है। प्रति वर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बड़े स्तर पर नागरिक सूचना पट्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मनरेगा योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों पर नागरिक सूचना पट्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है।जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता है। एक परिवार के आत्मनिर्भर होने से समाज की महत्वपूर्ण कड़ी मजबूत होती है और जब ऐसी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है तथा विकसित भारत की संकल्पना साकार होती है। विकसित भारत के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि विकसित होना भी आवश्यक है।

लोकभवन के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस की तत्परता से बचाई गई जान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। थाना हजरतगंज क्षेत्र में लोकभवन गेट संख्या-3 के पास एक महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई है। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया और उसे थाना हजरतगंज लाकर पूछताछ की जा रही है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को लगभग 12:40 बजे संध्या सिंह पत्नी सुखदेव सिंह, निवासी न्यू श्रीनगर थाना मानकनगर, हाल निवासी इंदिरानगर थाना गाजीपुर, लोकभवन गेट संख्या-3 के पास पहुंचीं और अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास करने लगीं। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित रोक लिया और थाना हजरतगंज लाया गया, जहां अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।प्रारम्भिक पूछताछ में पता चला है कि महिला का अपने पड़ोसी के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। महिला के अनुसार, थाना मानकनगर क्षेत्र में चल रहे इस भूमि विवाद को लेकर वह राजस्व विभाग में कई बार शिकायत कर चुकी हैं। 16 फरवरी 2026 को राजस्व विभाग द्वारा पुलिस की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराई गई थी, जिससे वह असंतुष्ट बताई जा रही हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर इकबाल नामक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है और वह उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही हैं।पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इससे पूर्व 27 फरवरी 2026 को भी महिला द्वारा लोकभवन के पास आत्मदाह का प्रयास किया गया था।

लखनऊ में 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित होगी छठवीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गो सेवा आयोग तथा अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसलों के अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, तेलंगाना के संयुक्त तत्वावधान में 08 से 10 अप्रैल 2026 तक छठवीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। "विकसित कृषि-विकसित भारत 2047 के लिए कृषि का रूपांतरण" विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में किया जाएगा।इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शामिल होना प्रस्तावित है, जबकि अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025-26 के अंतर्गत चयनित 15 उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा।

कैबिनेट ने 49 बस स्टेशनों के विकास और नई भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों को दी मंजूरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन निगम से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 49 बस स्टेशनों को विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इन बस स्टेशनों का विकास निर्माण, संचालन और हस्तांतरण पद्धति पर किया जाएगा।उन्होंने बताया कि बुलंदशहर जनपद के नरौरा, बलरामपुर जनपद की तुलसीपुर तहसील तथा हाथरस जनपद की सिकंद्राराऊ तहसील में बस स्टेशन निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन निगम द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति पर बस स्टेशनों के विकास के द्वितीय चरण में इन 49 बस स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इन बस स्टेशनों पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे खरीदारी परिसर, चलचित्र गृह सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निवेशकों की तकनीकी क्षमता की शर्त को 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पात्र परियोजनाओं में निवेशकों की अर्हता की समय सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बनने वाले बस स्टेशनों पर निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रस्तावित स्थलों पर समान भू-निर्माण अनुपात 2.5 निर्धारित किया गया है तथा भूमि आवरण की निःशुल्क अनुमति प्रदान की जाएगी। लीज अवधि समाप्त होने पर यदि विकासकर्ता स्वामित्व वापस नहीं करता है तो भूमि का स्वामित्व स्वतः ही परिवहन निगम को प्राप्त हो जाएगा।परिवहन मंत्री ने बताया कि बुलंदशहर में बस डिपो पूर्व में परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की लीज भूमि पर संचालित किया जा रहा था, जिसकी लीज अवधि समाप्त हो गई है।

संक्षेप

चेक बाउंस के मामलों में वांछित अभियुक्त गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार

लखनऊ। थाना महानगर पुलिस टीम ने गैर जमानती वारंट के तहत वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से न्यायालय में निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।पुलिस के मुताबिक अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राम प्रसाद, निवासी भीखमपुर पेपरमिल थाना महानगर, लखनऊ के विरुद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय कक्ष संख्या-1, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 113681/23, 113682/23 व 113683/23 धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।बताया गया कि अभियुक्त लोगों से चेक के माध्यम से धनराशि लेता था और बदले में चेक देता था, जो बाद में भुगतान के समय बाउंस हो जाते थे। न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था।थाना महानगर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को उसके पते 539 ग/36, भीखमपुर पेपरमिल थाना महानगर, लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की आयु लगभग 40 वर्ष बताई गई है।इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक आलोक कुमार तथा कांस्टेबल बिरंजन पाल शामिल रहे। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में वांछित अभियुक्त गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार

लखनऊ। थाना हजरतगंज पुलिस टीम ने न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के तहत एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।पुलिस के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 6427/17, अपराध संख्या 134/17 धारा 279, 304ए और 427 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वांछित अभियुक्त हर्ष कुमार साहू पुत्र संजय कुमार साहू, निवासी 188/74 हाजा दुर्गा प्रसाद, मसकगंज थाना वजीरगंज, लखनऊ के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।पुलिस टीम ने वारंट में अंकित पते पर दबिश देते हुए अभियुक्त को वारंट से अवगत कराया और उसे उसके निवास स्थान थाना वजीरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की आयु लगभग 36 वर्ष बताई गई है।गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय में पेश किया जा रहा है।इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रामकरन सिंह तथा उपनिरीक्षक अरुण कुमार, थाना हजरतगंज शामिल रहे।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में रोजगार शिविर, 270 अभ्यर्थियों का चयन

लखनऊ। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप संचालित मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में 06 एवं 07 अप्रैल 2026 को मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा खरखौदा, सोनीपत (हरियाणा) इकाई के लिए रोजगार चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा।संस्थान के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि इस प्रकार के रोजगार चयन शिविरों से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को चयनित करने का अनुरोध किया तथा चयनित अभ्यर्थियों को समय पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।प्रशिक्षण, परामर्श एवं नियोजन अधिकारी एम.ए. खां ने जानकारी दी कि रोजगार चयन शिविर में लगभग 1000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत कुल 270 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 32,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। रोजगार शिविर के सफल आयोजन में एक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों सहित संस्थान के अनुदेशक जेड रहमान का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

साइकिल से टक्कर मारकर रुपये उड़ाने वाले अंतरराज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सर्विलांस प्रकोष्ठ पुलिस उपायुक्त मध्य तथा थाना हजरतगंज की संयुक्त पुलिस टीम ने साइकिल से टक्कर मारकर रुपये चोरी करने वाले अंतरराज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना सहित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त साइकिल तथा चोरी किए गए रुपये भी बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार 20 मार्च 2026 को वादी बलराम साधवाणी पुत्र स्वर्गीय नारायण दास निवासी इंदिरानगर, लखनऊ ने सूचना दी थी कि 16 मार्च 2026 को दो अज्ञात व्यक्तियों ने साइकिल से टक्कर मारकर गिराने का प्रयास किया और संभालने का दिखावा करते हुए उनकी जेब में रखे 50 हजार रुपये निकाल लिए। इस संबंध में थाना हजरतगंज में धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना के खुलासे के लिए थाना हजरतगंज पुलिस तथा सर्विलांस प्रकोष्ठ की टीम द्वारा लगातार सुरागरसी और पतारसी की गई। तकनीकी सहायता और जांच के आधार पर 06 अप्रैल 2026 की रात लगभग 11:15 बजे चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में बिसारत पुत्र शराफत निवासी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, वसीम उर्फ शाहिल पुत्र शहजाद निवासी करूला जाहिद नगर थाना कटघर मुरादाबाद, अरुण कुमार उर्फ ठाकुर पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी उडपुरा थाना कटघर मुरादाबाद तथा सचिन चौहान पुत्र जगमोहन सिंह निवासी गांधी नगर थाना कटघर मुरादाबाद शामिल हैं।पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग पहले अपने शिकार का पीछा करते थे। गिरोह का एक सदस्य साइकिल से चलता था और अन्य सदस्य पीछे-पीछे चलते थे। मौका देखकर साइकिल से टक्कर मार देते थे और व्यक्ति को संभालने के बहाने उसकी जेब से रुपये और सामान निकालकर भीड़ में गायब हो जाते थे।

सहायक प्राध्यापक पुनर्परीक्षा 18 व 19 अप्रैल को, छह जनपदों में 53 परीक्षा केंद्र निर्धारित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (विज्ञापन संख्या-51) चयन पुनर्परीक्षा का आयोजन 18 एवं 19 अप्रैल 2026 को प्रदेश के छह जनपद— आगरा ,मेरठ लखनऊ ,प्रयागराज ,गोरखपुर एवं Varanasi में प्रस्तावित 53 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दोनों दिनों में दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 18 एवं 19 अप्रैल को विभिन्न विषयों के लिए तिथि एवं पाली के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, भाषा एवं अन्य विषयों के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है।

उपनिरीक्षक भर्ती में पद बढ़ाने और पारदर्शिता की मांग, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक भर्ती 2025 में पद वृद्धि तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।बताया गया कि उपनिरीक्षक भर्ती 2025-26 में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति तथा वर्तमान भर्ती प्रक्रिया से संबंधित गंभीर चिंताओं को व्यक्त किया है।अभ्यर्थियों ने बताया कि यह भर्ती लगभग पांच वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है, जिसके कारण अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस भर्ती परीक्षा में लगभग 10.77 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के कई पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिन्हें इसी भर्ती प्रक्रिया में पद वृद्धि के माध्यम से भरा जा सकता है।प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व की उपनिरीक्षक भर्ती वर्ष 2020-21 में कुल 9534 पदों पर नियुक्ति की गई थी, जबकि वर्तमान भर्ती में पदों की संख्या लगभग आधी से भी कम है, जो मौजूदा परिस्थितियों में अपर्याप्त प्रतीत होती है।अभ्यर्थियों ने यह अपेक्षा भी व्यक्त की है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ ही उनके अंकपत्र (सामान्यीकृत अंक एवं विषयवार अंक सहित) जारी किए जाएं। साथ ही अंतिम चयन के बाद यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो प्रतीक्षा सूची जारी कर रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके।

बीबीएयू के भूविज्ञान विभाग के दो विद्यार्थियों का सीमेंट कंपनी में चयन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के भूविज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विभाग के दो मेधावी विद्यार्थी ऋषि राज झा और शिवा मिश्रा का चयन देश की अग्रणी सीमेंट निर्माण कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा किया गया है।इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, समर्पण और विभाग में उपलब्ध उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है।यह चयन कंपनी द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। तीन माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह 20 हजार रुपये का वजीफा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के बाद उन्हें 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसमें वार्षिक 5.5 लाख रुपये का वेतन पैकेज दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 6 लाख रुपये वार्षिक वेतन के साथ स्थायी नियुक्ति भी दी जा सकती है, जिसमें यात्रा एवं आवास भत्ता भी शामिल रहेगा।प्रशिक्षण के दौरान चयनित विद्यार्थी कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं में भाग लेंगे, जहां उन्हें चूना पत्थर के भंडारों का सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक विश्लेषण, खनिज संसाधनों का मूल्यांकन तथा सीमेंट उद्योग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक कार्य वातावरण को समझने तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

यह उपलब्धि न केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए बल्कि भूविज्ञान विभाग और विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व और प्रेरणा का विषय मानी जा रही है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रो. नरेंद्र कुमार ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विभाग के सभी शिक्षकों ने भी इस उपलब्धि को विभाग के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगी।

मैनपुरी में 63 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा भव्य सांस्कृतिक केंद्र

लखनऊ। जनपद मैनपुरी विगत नौ वर्षों से राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। इसी के चलते यहां चौमुखी विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं का सृजन किया गया है तथा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया है। मैनपुरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि होने के साथ ही अनेक प्राचीन धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। इसी क्रम में मैनपुरी को नई पहचान देने के उद्देश्य से 63 करोड़ रुपये की लागत से यहां एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया जा रहा है। मैनपुरी अब विकास के मामले में प्रदेश के अग्रणी जनपदों की श्रेणी में स्थापित हो चुका है।

यह जानकारी मैनपुरी सदर से विधायक एवं पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि प्राचीनकाल में यहां चौहान वंश के शासक महाराजा तेज सिंह जूदेव का शासन था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अमीनाबाद इंटर कॉलेज में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अमीनाबाद इंटर कॉलेज में "स्वच्छता की संस्कृति निर्माण" विषय पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वच्छता शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।कार्यक्रम के दौरान महापौर ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को यदि दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने घर, विद्यालय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं।महापौर ने हाथों की स्वच्छता को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत कई संक्रामक रोगों से बचाती है। उन्होंने यह भी कहा कि आसपास पानी जमा न होने देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे मच्छरों का प्रजनन होता है और डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।उन्होंने अपने संबोधन में वैज्ञानिक सोच अपनाने पर भी जोर दिया और कहा कि समाज में जागरूकता लाने के लिए अंधविश्वासों से दूर रहना तथा विज्ञान आधारित सोच अपनाना आवश्यक है। बच्चों से उन्होंने आग्रह किया कि वे स्वच्छता का संदेश अपने परिवार और समाज तक पहुंचाएं।इस अवसर पर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उपविजेता रजनीश गुप्ता, पार्षद मुकेश सिंह मोंटी, प्रधानाचार्य साहब लाल मिश्रा, जिला समन्वय अधिकारी अतुल तिवारी, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक अमित शुक्ला, प्रबंधक शशिकांत सिंह, डॉ. एम. एल. पॉल, दिलीप सिंह, डॉ. कृष वर्गिस सहित विद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया और सभी ने मिलकर स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस पहल के लिए योजना अंतरराष्ट्रीय (भारत अध्याय) तथा स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े सभी आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

बच्चों की जिंदगियां बेतरतीब करते स्मार्टफोन

भारत में 50 प्रतिशत से अधिक किशोर रोज चार घंटे से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे पढ़ाई, खेल और परिवार से संवाद का समय कम हो जाता है। इससे मोटापा, आलस्य, थकान और कमजोर स्टैमिना की समस्याएं बढ़ रही हैं। 60 प्रतिशत बच्चों में नींद पूरी नहीं होने से उनमे चिड़चिड़ापन और गुस्सा की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा अपने भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता कमजोर होने लगती है। चार घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम वाले 25.9 प्रतिशत बच्चे अवसादग्रस्त पाए गए जबकि इससे कम स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में केवल 9.5 प्रतिशत ही अवसाद की समस्या पाई गई। तकनीक ने मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म और गेमिंग व ऐसे ही अन्य कई ऐप्स की लत से विश्व भर के बच्चों को एक ख़तरनाक और गंभीर स्थिति में ला दिया है। बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकार बढ़ रहे हैं, वे साइबर अपराधों के शिकार हो रहे हैं । मोबाइल के कारण बच्चे आत्महत्या कर लगे हैं। बच्चों के सामाजिक व शैक्षिक जीवन पर इसका बुरा असर हो रहा है ।

140 करोड़ की जनसँख्या के इस देश में दिसंबर 2025 तक 124.42 करोड़ मोबाइल धारक और 1.02 करोड़ से अधिक इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हो गए हैं। हर माह प्रति व्यक्ति औसत डाटा की खपत 25 जीबी वाला हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा दूरसंचार बाजार है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन कक्षाए संचालित कर बच्चों की पढ़ाई करवाने के सरकारी फरमान के बाद स्कूली बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देना पालकों की विवशता हो गई। हालाकि केंद्र के सरकारी और ऊँची फीस वाले निजी स्कूलों में इन ऑनलाइन कक्षाओं का विधार्थियों ने भरपूर लाभ लिया और अपनी सीखना जारी रखा, लेकिन लाखों सरकारी व छोटे गैर-सरकारी स्कूलों में यह मात्र औपचारिकता ही रहा और विधार्थी सीखने में पिछड़ गए। इस समूची कवायद का हश्र यह हुआ कि आदिवासी व ग्रामीण बसाहटों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के अधिकतर बच्चों को छोड़ कर देश भर के करोड़ो बच्चों के हाथों में यह उपकरण आ गया। सूचना, ज्ञान, संचार, वित्तीय लेनदेन और नियंत्रित मनोरंजन जैसी मूल आवश्यकताओं पीछे छोड़ ज्यादातर बच्चे इस उपकरण का व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, यू-टयूब व गेमिंग के एप्स, सेल्फी, विडियो व रील बनाने आदि में जरुरत से बेहिसाब ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। घंटों स्क्रीन पर अपनी आँखें और ध्यान गड़ाए रख आभासी दुनिया में विचरण करने लगते हैं। यह स्थिति कई चिंताए पैदा करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन जैसी मानक संस्थाओं के अध्ययनों के अनुसार भारत में 2 साल से कम उम्र के 61 प्रतिशत बच्चे स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 2 साल तक के बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ही नहीं दिखानी चाहिए। भारत में 50 प्रतिशत से अधिक किशोर रोज चार घंटे से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे पढ़ाई, खेल और परिवार से संवाद का समय कम हो जाता है। इससे मोटापा, आलस्य, थकान और कमजोर स्टैमिना की समस्याएं बढ़ रही हैं। 60 प्रतिशत बच्चों में नींद पूरी नहीं होने से उनमे चिड़चिड़ापन और गुस्सा की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा उनमें भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता कमजोर होने लगी है। चार घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम वाले 25.9 प्रतिशत बच्चे अवसादग्रस्त पाए गए जबकि इससे कम स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में केवल 9.5 प्रतिशत ही अवसाद की समस्या पाई गई। बाज़ार की जरूरतों के मद्देनज़र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और गेमिंग सहित कई लुभावनी एप्स को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह बच्चे लंबे समय तक मोबाइल से बंधे रहें और इसके इस्तेमाल की लत के शिकार हो जावें। लत में पड़ कर वे देर रात तक जाग रहे हैं, नींद पूरी न होने से शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है, आत्म विश्वास कम हो रहा है। दूर तक देखने की क्षमता कम होने सहित नेत्र दोषों के शिकार हो रहे बच्चे। स्थिति यह हो जाती है कि वे मोबाइल के उपयोग से अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। बार-बार व्हाट्सअप, फेसबुक या इंट्राग्राम पर पोस्ट चेक करते हैं। यहाँ तक बाथरूम में भी मोबाइल साथ रहता है। मोबाइल के बिना रहने, नेटवर्क न मिलने या फोन खो जाने का तर्कहीन डर उनमे बना रहता है। पोस्ट पर आने वाली लाइक्स और कंमेंटस उनके इए व्यक्तित्व की स्वीकृति का आधार बन उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती हैं। यह स्थिति नोमोफोबिया नामक एक आधुनिक मानसिक विकार है, जो 12 से 23 वर्ष के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है।

पता नहीं आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा

ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ने की घोषणा के 10 साल हुए हैं तो 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के भी छह साल होने जा रहे हैं।

अजीत द्विवेदी

दस साल हो गए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सात फरवरी 2016 को ओडिशा के पारादीप में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की एक रिफाइनरी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही थी। उन्होंने उस समय एक लक्ष्य भी तय किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए विदेशी निर्भरता को 10 फीसदी तक कम करेगा। उस समय भारत 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता था।

आज 10 साल बाद भारत का कच्चे तेल का आयात 85 फीसदी से ज्यादा हो गया है। यानी जहां दस फीसदी आयात कम होना था वहां पांच फीसदी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने आयात पर निर्भरता 10 फीसदी घटाने के लक्ष्य के साथ साथ यह भी कहा था कि ऊर्जा जरुरतों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चार क्षेत्र बताए थे, जहां काम किया जाना था। इसमें इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाना और तेल, गैस आदि की खोज को प्रोत्साहित करना शामिल था।

सोचें, 10 साल पहले ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना कितना अच्छा लगा होगा! उसमें भी तात्कालिक लक्ष्य आयात में 10 फीसदी की कमी का रखा गया था। एक ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया। लेकिन 10 साल के बाद देश कहां पहुंचा? आज स्थिति यह है कि भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों के लिए दूसरे देशों पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल के मामले में भारत की निर्भरता बढ़ी है। हकीकत यह है कि जिस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का संकल्प किया गया था उनके लिए भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है पर उसकी लिए बैटरी और दूसरी कई तकनीकी चीजें चीन से आएंगी। इसी तरह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का मामला है तो उसके लिए भी सोलर प्लेट्स में लगने वाले कल पुर्जे और दूसरे उपकरण चीन से आएंगे। सोचें, हम तेल के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के मामले में भी दूसरे देशों पर निर्भर हो गए हैं।

ऐसा नहीं है कि 10 साल में इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन थोड़े से काम होने से तो देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन जाएगा? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल आयात में 10 फीसदी की कमी की जाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोई योजना होगी, लंबे समय की कोई प्लानिंग होगी! फिर किसने उनको उस योजना पर काम नहीं करने दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आत्मनिर्भरता की योजना के नाम पर थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाने की योजना हो? जब इतनी बड़ी घोषणा की जाती है तो उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा प्रयास करना होता है। उस प्रयास में स्पष्ट कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि समय समय पर इस तरह की बातें करके प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा तो दिया कि वे देश की समस्या को समझ रहे हैं और उसका समाधान करना चाहते हैं। लेकिन समाधान की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उन्होंने 2016 के बाद तेल आयात कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात अनेक बार कही। लेकिन सवाल है कि क्या वे देख नहीं रहे थे कि उनकी बातों या दावों में और देश की वास्तविकता में कितना अंतर है?

आज जब संकट देश के सामने आया तो सबका ध्यान इस वास्तविकता की ओर गया है। ईरान में जंग शुरू हुए 12 दिन हुए हैं और भारत में हाहाकार मचा है। भारत सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा लागू करना पड़ा है। हालांकि रसोई गैस का मामला कालाबाजारी का भी है। लेकिन यह भी सही है कि किल्लत बढ़ रही है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी की जरुरतों का 80 फीसदी से ज्यादा खाड़ी के देशों से आयात करता है और उसके भंडारण की भी वैसी व्यवस्था देश में नहीं है, जैसी कच्चे तेल के लिए है। इसलिए संकट तो है। तभी देश भर में होटल और रेस्तरां बंद हो रहे हैं और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति के नियम बनाने पड़े हैं। सरकार ने घरेलू आवंटन को सौ फीसदी रखने को कहा है लेकिन उद्योगों और व्यावसायिक संस्थाओं के आवंटन में 20 से 30 फीसदी की कटौती हुई है। एलपीजी के अलावा तेल का संकट भी है तभी विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कम होने से उर्वरक से लेकर प्लास्टिक उद्योग तक करीब 75 उद्योग हैं, जहां असर हुआ है। उर्वरक के उत्पादन पर असर होगा तो अंततः उससे खाद्यान्न सुरक्षा भी प्रभावित होगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ने की घोषणा के 10 साल हुए हैं तो 'आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी छह साल होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की घोषणा भी हुई थी। हालांकि वह पूरी तरह से क्रेडिट गारंटी की योजना थी। किसी को मदद के तौर पर इसमें से एक रुपया नहीं मिला, बल्कि सबको कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वह अलग कहानी है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तय किया गया कि भारत में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, युवा शक्ति का अधिकतम इस्तेमाल होगा, देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, तकनीक के क्षेत्र में देश को बेहतर बनाया जाएगा और मांग को पूरा करना की आत्मनिर्भर व्यवस्था बनेगी। लेकिन छह साल के बाद कोई नया क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें आत्मनिर्भरता बनी है। जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी लगभग उसी समय भारत ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकने के लिए एक नियम बनाया था। अब उस नियम में ढील दे दी गई है। ऐसा लग रहा था कि चीन से दूरी बना कर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा लेकिन छह साल के बाद भारत फिर उसी रास्ते पर लौटा है। ध्यान रहे चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 10 लाख करोड़ रुपए के करीब है। भारत अगर तेल और ऊर्जा जरुरतों के लिए खाड़ी देशों या रूस, अमेरिका पर निर्भर है तो फार्मा से लेकर फार्म सेक्टर तक और ईवी से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तक और रोजमर्रा की जरुरत की चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। पता नहीं आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा अभी तो निर्भरता कम होती भी नहीं दिख रही है।

टिप्पणी

डेमोग्रैफिक डिविडेंड गंवा देने का खतरा

जो देश अपनी युवा श्रमशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, उनके संबंध में आम समझ है कि वे धनी होने से पहले बूढ़ा हो जाते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर डेमोग्रैफिक डिविडेंड गंवा देने का खतरा मंडरा रहा है।

युवा आबादी के संभावित लाभ को भारत गंवाने जा रहा है- यह निष्कर्ष है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के 'भारत में कामकाज की स्थिति-2026' रिपोर्ट का। इसके मुताबिक 2030 में युवा आबादी (15- 29 वर्ष) अपनी चरम संख्या पर पहुंच जाएगी। उसके बाद इसमें गिरावट आने लगेगी। फिलहाल 36.7 करोड़ युवा इस उम्र वर्ग में हैं, जो कुल कामकाजी उम्र की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। मगर उनमें से 26.3 करोड़ ना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ना रोजगार में हैं। अतः उनके श्रमशक्ति का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'आने वाले दशक में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार सृजन की गति यह तय करेगी कि डेमोग्रैफिक डिविडेंड आर्थिक लाभ में तब्दील होता है या नहीं।'

मगर रोजगार की सूरत यह है कि सिर्फ सात प्रतिशत पुरुष स्नातकों को डिग्री लेने के बाद पहले साल में नियमित वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। ह्वाइट कॉलर जॉब्स की बात करें, तो यह संख्या महज 3.7 फीसदी है। तो रिपोर्ट में कहा गया है- 'ये संख्याएं चिंताजनक सूरत की झलक हैं। सुरक्षित ह्वाइट कॉलर जॉब ढूंढना अत्यधिक दुर्लभ घटना बनी हुई है।' वैसे चिंताजनक अनेक अन्य आंकड़े भी रिपोर्ट में हैं। उनमें एक बेरोजगार स्नातकों की विस्फोटक ढंग से बढ़ती गई संख्या है। 2004 में 30 लाख स्नातक बेरोजगार थे। यह संख्या 2011 में 40 लाख पहुंच गई।

2011-17 में इसमें बेहद तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई। 2023 तक ये तदाद एक करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। इन स्थितियों के साथ कोई देश आर्थिक महाशक्ति बनने की कैसी उम्मीद जोड़ सकता है? जो देश अपनी युवा श्रमशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, उनके संबंध में आम आर्थिक समझ है कि वे धनी होने से पहले बूढ़ा हो जाते हैं। विश्व बैंक की श्रेणी के मुताबिक भारत लगभग तीन हजार डॉलर सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ अभी भी निम्न-मध्यम आय वर्ग वाला देश है। यानी धनी होने के पहले उसे उच्च मध्य वर्ग की श्रेणी (4,500 से 14000 डॉलर) पार करनी है। जबकि युवा आबादी की संख्या में वृद्धि के अब सिर्फ चार साल बाकी हैं।

ब्लॉग

भारत के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी

अजीत द्विवेदी

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले में भारत पक्षकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध शुरू होने से दो दिन पहले जरूर इजराइल की यात्रा पर गए थे। लेकिन भारत इस सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद इस युद्ध का बड़ा असर भारत के ऊपर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर व्यापक असर होगा तो साथ ही खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों और पेशेवरों द्वारा भेजे जाने वाले रेमिटेंसेज यानी उनके पैसे पर भी असर होगा। इसके अलावा भारत की कूटनीति और सामरिक नीति भी प्रभावित होगी। सवाल है कि क्या भारत इस युद्ध की संभावना को देख रहा था और उसके असर से निपटने की कोई तैयारी हुई थी? दोनों का जवाब नकारात्मक है। अगर भारत युद्ध की वास्तविक संभावना देख रहा होता तो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर नहीं जाते। जब युद्ध की संभावना नहीं दिख रही थी तो जाहिर है कोई तैयारी भी नहीं होगी।

ध्यान रहे भारत किसी सैन्य गठजोड़ का हिस्सा नहीं है और इजराइल के साथ साथ ईरान से भी पारंपरिक रूप से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। इसलिए भारत के लिए यह एक कठिन परीक्षा की घड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ईरान द्वारा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर किए जा रहे हमले को लेकर भी भारत ने चिंता जताई है और इसकी आलोचना की है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर भारत की चुप्पी से इसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध में उन्होंने कई बार यह बात कही है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले में भारत यह बात नहीं कह रहा है। यह भी रणनीतिक स्वायत्तता के भारत के दावे पर सवाल खड़े करता है।

बहरहाल, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के असर को समझना हो तो सबसे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से इसे देखना होगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 81 फीसदी हिस्सा आयात करता है। पश्चिम एशिया इस आयात का प्रमुख स्रोत है। अगर ईरान होरमुज की खाड़ी को बाधित करता है और लाल सागर में हूती द्वारा हमला करके उस क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जाता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल होरमुज की खाड़ी से होकर गुजरता है। लेकिन भारत का 40 फीसदी तेल इस रास्ते से आता है। सोचें, अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अब अगर खाड़ी से तेल की आपूर्ति प्रभावित होती

है तो भारत की मुश्किल बढ़ेगी। इससे भारत पर अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने के दबाव बढ़ेगा।

तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल संभव है। अभी यह 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है और अगर जंग जारी रहती है तो यह एक सौ डॉलर प्रति बैरल तक या उससे ऊपर भी जा सकता है। इससे भारत के आयात बिल में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसका असर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ेगा और पहले से दबाव झेल रहा रुपया और दबाव में आएगा। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करती है तो उससे आम उपभोक्ताओं पर असर होगा और साथ ही परिवहन, उर्वरक, बिजली और विमानन सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। अंततः इसका बोझ भी जनता पर ही पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका असर भारतीय रिजर्व बैंक की उदार ब्याज नीतियों पर भी पड़ेगा। केंद्रीय बैंक को सख्ती बरतनी होगी। अगर ब्याज दर बढ़ते हैं तो विकास दर में भी कमी आएगी।

एक अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों में 90 लाख से एक करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान जैसे देशों में भारतीय समुदाय की बड़ी मौजूदगी है। बाहर से भारतीय पेशेवेर जो रेमिटेंस यानी पैसा भेजते हैं उसका एक तिहाई से ज्यादा करीब 35 फीसदी हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यह बड़ी रकम होती है, जिसका कई राज्यों की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होता है। अगर ईरान का युद्ध व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदलता है, तो सभी खाड़ी देशों की सुरक्षा स्थिति प्रभावित हो सकती है। ध्यान रहे ईरान ने लगभग सभी खाड़ी देशों पर हमला शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी एक बड़ी कूटनीतिक और मानवीय चुनौती बन जाएगी। भारत ने यमन और यूक्रेन जैसे संकटों में बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाए हैं, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में संकट कहीं अधिक जटिल हो सकता है। रेमिटेंसेज में कमी आएगी, जिससे केरल और तेलंगाना से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक में लाखों परिवार प्रभावित होंगे।

ध्यान रखने की जरुरत है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार के जरिए पश्चिम एशिया और यूरोप से जुड़ा है। युद्ध की स्थिति में इस रास्ते में व्यापार प्रभावित होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग बीमा महंगा होगा। इससे ऊर्जा के अलावा पेट्रोकेमिकल, फार्मा और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। यदि समुद्री मार्गों में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत को वैकल्पिक रास्तों और रणनीतियों पर तेजी से काम करना होगा।

भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास में बड़ा निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन इंटरव्यू में इसे बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं। इस बंदरगाह से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है और भारत को क्षेत्रीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलता है। युद्ध बढ़ने की स्थिति में यह परियोजना ठप पड़ सकती है, जिससे भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएं प्रभावित होंगी। अगर यह क्षेत्र अस्थिर होता है तो चीन और अन्य शक्तियों को अपना असर बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

भारत के सामने आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा बड़ी चुनौती कूटनीतिक है। ईरान निश्चित रूप से चीन और रूस के ज्यादा करीब है लेकिन भारत के संबंध ऐतिहासिक और ऊर्जा आधारित रहे हैं। दूसरी ओर इज़राइल और अमेरिका के साथ भारत की रक्षा और रणनीतिक साझेदारी बेहद मजबूत है। ऐसे में भारत के लिए तटस्थ रहना और संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। भारत मल्टी एलायनमेंट की नीति पर काम कर रहा है। ऐसे में वह दोनों पक्षों से युद्ध खत्म करने और शांति बनाने की अपील कर सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उसे एक स्पष्ट पोजिशन लेनी होगी। अगर एशिया में हो रहे सैन्य टकराव में भी भारत मूक दर्शक ही रहता है तो वह वैश्विक मंच पर एक मजबूत मैसेज देने का मौका गंवा देगा। युद्ध के बाद इस क्षेत्र में हो सकता है कि अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बढ़े। साथ ही इस क्षेत्र में नया इराक बनने की संभावना भी दिख रही है, जिससे अस्थिरता बढ़ेगी और स्थायी रूप से तनाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए खरीद में विविधता लाने पर गंभीरता से विचार करना होगा और वैकल्पिक व्यापार मार्गों की तलाश और विकास भी करना होगा।

'केवल संदेह पर कोई दोषी नहीं हो सकता...' रेप केस में 11 साल काटी जेल, अब हाईकोर्ट से हुए बरी

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म और नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी कर दिया। आरोपी निर्मल कुमार ने 11 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे बिताए थे। हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक मामलों में केवल अनुमान या संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने 20 सितंबर 2010 के उस मामले में 2018 के फैजाबाद सत्र न्यायालय के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया।

20 सितंबर 2010 को फैजाबाद में पड़ोस में रहने वाले निर्मल कुमार पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। तीन दिन बाद पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने पड़ोसी निर्मल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सत्र अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निर्मल कुमार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें आखिरकार उन्हें राहत मिल गई।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में योनि स्वाब पर मानव वीर्य की मौजूदगी जरूर पाई गई थी, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई और वैज्ञानिक जांच नहीं की गई कि वह वीर्य अपीलकर्ता निर्मल कुमार का ही था। खंडपीठ ने सख्त शब्दों में कहा कि डीएनए टेस्ट या वीर्य का मिलान न कर पाना जांच एजेंसी की गंभीर चूक थी। कोर्ट ने आगे कहा कि बिना ठोस सबूत के केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को 11 साल तक जेल में बंद रखना न्यायोचित नहीं है। अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निर्मल कुमार की रिहाई का आदेश दे दिया।

केएनआईटी में अनियमित तरीके से हो रही पदोन्नति की शासन में हुई शिकायत

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। केएनआईटी, सुल्तानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति से करोड़ों रुपए की वित्तीय क्षति होगी। शिकायत कर्ता ने बताया कि इस अनियमित पदोन्नति के मुख्य सूत्रधार निदेशक राजीव उपाध्याय हैं। अपर निदेशक कोषागार/पेंशन, अयोध्या नामित वित्त सचिव ने प्रशासनिक परिषद की 62वीं कार्यवृत्ति के द्वारा 7 वर्ष के अंदर पीएचडी न होने पर इंक्रीमेंट न रोकने एवं बिना पीएचडी प्रमोशन के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसके क्रम में कैस के अंतर्गत हुई पदोन्नति का पूरा परीक्षण कराए जाने हेतु प्रशासनिक परिषद ने एक जांच समिति का गठन किया था। समिति की जांच आख्या पर समिति सचिव वित्त (62वीं प्रशासनिक परिषद द्वारा अनियमित पदोन्नति पर आपत्ति करने वाले अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, अयोध्या) के हस्ताक्षर नहीं है। जो आपत्तिकर्ता के साथ-साथ समिति की सदस्य भी थे। जिससे प्रथम दृष्टि में पता चल रहा है कि जो पदोन्नति होने जा रही वह संदिग्ध है। शासनादेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विपरीत केएनआईटी के निदेशक ने समिति की अपूर्ण रिपोर्ट को 63 वीं प्रशासनिक परिषद के मिनट पर अनुमोदित करा कर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उक्त प्रकरण पूर्व की कई प्रशासनिक परिषद की बैठक में निरस्त किया जा चुका है। केएनआईटी के निदेशक के द्वारा संस्थान के पूर्व निदेशक के आदेश सख्या -141/3/274/2006 दिनाक 17:06:2006 का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा, जिसके द्वारा सात वर्ष के अंदर पीएचडी न करने पर दिया गया पदनाम निरस्त करने का आदेश दिया गया है और प्राविधिक शिक्षा-अनुभाग 1 के शासनादेश दिनांक 05-11-2018 द्वारा पीएचडी न करने तक वेतन वद्धि रोकने का आदेश दिया गया था तथा निदेशक, केएनआईटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश (स्पेशल लीव पेटिशन सिविल डायरी नंबर 1917/2021) का अनुपालन नहीं जा रहा है। केएनआईटी के वेतन का आहरण वितरण जिलाधिकारी सुल्तानपुर के डीडीओ कोड से होता है। अनियमित भुगतान न हो पाए इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को सजग रहना होगा। देखना यह है कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा शासनादेश की विपरीत हो रही पदोन्नति पर क्या कार्यवाही करते हैं? पदोन्नति के प्रकरण को अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, अयोध्या के स्पष्ट मार्गदर्शन बाद ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना ही उचित होगा।

अनारकली का 70 साल का बॉयफ्रेंड, पति को रास ना आया अफेयर, कर डाला ऐसा कांड

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के यमुनानगर जोन अंतर्गत नैनी पुलिस ने महज 36 घंटों के भीतर बुजुर्ग हजारीलाल की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस हत्याकांड के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, 70 वर्षीय हजारीलाल की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी प्रेमिका के 66 वर्षीय पति रामलाल ने कुल्हाड़ी से काटकर की थी।

जांच में पता चला कि मृतक हजारीलाल (70) के आरोपी रामलाल की पत्नी अनारकली (65) के साथ पिछले 8 वर्षों से अवैध संबंध थे। इन संबंधों के कारण रामलाल के घर में कलह रहती थी और उसकी पत्नी उससे बात तक नहीं करती थी। इसी अपमान और नाराजगी के चलते रामलाल ने 10 दिन पहले ही हजारीलाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली थी।

2 और 3 अप्रैल की दरम्यानी रात, जब हजारीलाल बालू के ठेके पर चौकीदारी करते हुए सो रहे थे, तभी रामलाल कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा। रात करीब 2 बजे रामलाल ने सोते हुए हजारीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से वार किया। चोट लगते ही हजारीलाल चारपाई पर गिर गए, जिसके बाद आरोपी ने उनके चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ तीन-चार वार किए। हजारीलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी

हत्या के बाद आरोपी रामलाल कुल्हाड़ी को अपने घर ले गया और उसे बालू के ढेर में छिपा दिया। मृतक के बेटे सोनू की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नैनी पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर रामलाल को ग्राम धनुआ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। आरोपी को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है।

अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हुआ ज्ञान कुंज परिसर

सुलतानपुर। सरस्वती विद्या मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञान कुंज विवेकानन्द नगर सुल्तानपुर में मंत्रोच्चार के साथ आज दस नये इंटरैक्टिव पैनल का विधिवत उद्घाटन किया गया। ए आई तकनीक वाले युग में नवाचार आधारित नई ऊर्जा,नये संकल्प एवं उन्नत तकनीक के साथ नये शिक्षण सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। सम्पूर्ण वाई-फाई कनेक्टीविटी वाले परिसर में पहले से ही कई शिक्षण कक्ष इंटरैक्टिवपैनल समेत कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। विद्यालय को इसी सत्र में अत्याधुनिक तकनीक से शत-प्रतिशत सुसज्जित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि इसी सत्र में हमारे सभी कक्षा कक्ष इंटरैक्टिवपैनल की सुविधा से लैस होंगे। जिस पर हम पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रबंधक डाक्टर पवन कुमार सिंह ने कहा कि शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि होती रहे।

सुलह या तलाक... क्या होगा फाइनल? एडीएम ज्योति मौर्या ने दिया जवाब

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। क्या एडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक के बीच विवाद खत्म हो गया है? हाल ही में ऐसी चर्चाएं होनी शुरू हो गई थीं। हालांकि, ज्योति मौर्या ने इन खबरों को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सुलह की कोई संभावना नहीं है और उन्हें नहीं पता कि इस तरह की अफवाहें कहां से फैल रही हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ज्योति मौर्या ने स्पष्ट किया कि उनका तलाक अंतिम चरण में है और आने वाले दो महीनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह और आलोक मौर्या पहले ही अलग हो चुके हैं और अब किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस तरह की खबरें क्यों और किस मकसद से फैलाई जा रही हैं।

2010 में हुई थी ज्योति और आलोक की शादी

हाल ही में ज्योति मौर्या को प्रमोशन मिला है और उनकी नई तैनाती गाजियाबाद में एडीएम (अपर जिलाधिकारी) के पद पर हुई है।ज्योति और आलोक की शादी साल 2010 में हुई थी। शुरुआती वर्षों में दोनों के रिश्ते काफी अच्छे थे। साल 2015 में ज्योति मौर्या का पीसीएस में चयन हुआ और उन्हें एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिली। उस समय आलोक मौर्या पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। लेकिन नौकरी और जिम्मेदारियों में बदलाव के बाद दोनों के रिश्तों में धीरे-धीरे खटास आने लगी।

2023 में आलोक मौर्या ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

विवाद तब सार्वजनिक हुआ, जब साल 2023 में आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ज्योति पर भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति अर्जित करने और एक अधिकारी के साथ अफेयर के आरोप लगाए थे। आलोक का यह भी कहना था कि उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन सफलता मिलने के बाद रिश्ते बिगड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने प्रशासनिक जांच के आदेश दिए थे और एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। दोनों पक्षों से सबूत मांगे गए, लेकिन बाद में आलोक मौर्या ने अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके बाद समिति ने भी मामले को समाप्त मानते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

पहली मुलाकात से शादी तक का सफर... आईआईटी बाबा अभय सिंह की क्या है फ्यूचर प्लानिंग? पत्नी प्रतीका ने बताया

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी अनूठी आध्यात्मिक यात्रा से रातों-रात सुर्खियों में आए 'IIT बाबा' उर्फ अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री और लाखों का पैकेज छोड़कर संन्यास की राह चुनने वाले अभय सिंह अब विवाह बंधन में बंध गए हैं। हाल ही में वे अपनी पत्नी प्रतीका के साथ अपने पैतृक गांव सासरौली (झज्जर) पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शादी के बाद फ्यूचर प्लानिंग का खुलासा किया।

हरियाणा के झज्जर निवासी अभय सिंह ने बताया कि उनकी मुलाकात कर्नाटक के मंगलूरु की रहने वाली इंजीनियर प्रतीका से सद्गुरु के आश्रम (आदियोगी, कोयंबटूर) में हुई थी। दोनों की विचारधारा और अध्यात्म के प्रति झुकाव ने उन्हें साथ ला दिया। इस साल 15 फरवरी को उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला के पौराणिक अघंजर महादेव मंदिर में धार्मिक रीति-रिवाजों से शादी की और फिर 19 फरवरी को धर्मशाला में विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज की।

36 लाख का पैकेज छोड़कर अध्यात्म की राह

अभय सिंह का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2008 में JEE में 731वीं रैंक हासिल करने वाले अभय ने IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की। कनाडा में 36 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर काम करने के बाद, उन्होंने आंतरिक शांति की तलाश में करियर को अलविदा कह दिया। उनका मानना है कि विज्ञान जहां IQ (बुद्धि) बढ़ाता है, वहीं कला और अध्यात्म EQ (भावनात्मक बुद्धिमत्ता) को संतुलित करते हैं।

कांगड़ा में बनेगा ज्ञान का केंद्र

शादी के बाद अपने भविष्य के लक्ष्यों पर बात करते हुए अभय सिंह और उनकी पत्नी प्रतीका ने कहा कि वे अब 'श्री यूनिवर्सिटी' (Shri University) प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लोगों को प्राचीन ज्ञान और साधना की विभिन्न पद्धतियों से एक ही स्थान पर जोड़ना। हिमाचल के कांगड़ा में महादेव की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित होकर वे वहीं अपना केंद्र स्थापित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए संसार के कल्याण के लिए आध्यात्मिक कार्य जारी रखेंगे।

'मिशन शक्ति' कार्यक्रम आयोजित, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण पर दिया जोर

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत मंगलवार को सुल्तानपुर के पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार की अधिकांश योजनाएं महिलाओं, बेटियों और माताओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। 'नारी सम्मान मिशन शक्ति' के माध्यम से महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित हुआ है।

न्यू नोएडा में आने वाली जमीन के मालिक होंगे मालामाल, मुआवजा तय... कितना मिलेगा पैसा?

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। न्यू नोएडा (DNGIR) के सपनों को धरातल पर उतारने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्राधिकरण की हालिया बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए किसानों के लिए मुआवजे की नई दरें तय कर दी गई हैं। अब न्यू नोएडा के किसानों को भी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के बराबर ही मुआवजा दिया जाएगा।

लंबे समय से मुआवजे की दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। अब प्राधिकरण ने 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की है। यह दर यीडा के समान होने से क्षेत्र के करीब 80 गांवों के किसानों में संतोष बढ़ने की उम्मीद है। इस पारदर्शी नीति से भविष्य में भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाले विवादों की संभावना भी कम होगी।

न्यू नोएडा का विकास 'मास्टर प्लान 2041' के तहत चार चरणों में किया जाना है। भूमि अधिग्रहण की शुरुआती प्रक्रिया के लिए प्राधिकरण ने 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। पहले चरण में हजारों हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर वहां औद्योगिक और आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अधिकारियों का लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार कर निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

रोजगार और निवेश का बनेगा महा-केंद्र

न्यू नोएडा को एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहां बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। इससे न केवल नोएडा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह परियोजना आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभरेगी।

जेल में बंदी ने की बैरक के अंदर आत्महत्या

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। सुल्तानपुर जेल में पत्नी की हत्या के आरोपी एक बंदी ने आत्महत्या कर ली। धनपतगंज के चरथई निवासी नक्छेद का शव सोमवार रात जेल के बैरक में शौचालय के अंदर प्लास्टिक की रस्सी से लटका मिला। जेल कमांडेंट प्रांजल अरविंद ने बताया कि मृतक बंदी नक्छेद 25 मार्च से कारागार में निरुद्ध था। रात्रि करीब डेढ़ बजे शौचालय में उसका शव प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ पाया गया। नक्छेद (45 वर्ष) को अपनी पत्नी कुसुम (42 वर्ष) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे 25 मार्च को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। घटना 24 मार्च को हुई थी। नक्छेद गांव में लिंटर डालने का काम कर रहा था, जब उसने अपनी पत्नी कुसुम को फोन किया। कुसुम के फोन न उठा पाने पर नक्छेद नाराज हो गया। रात करीब 12 बजे घर लौटने पर उसने पत्नी कुसुम को पीटना शुरू कर दिया। उनके दो छोटे बच्चे, उदयभान (9 वर्ष) और दीक्षा (8 वर्ष), जब अपनी मां को बचाने आए, तो नक्छेद ने उन्हें भी धक्का दे दिया। उसने बच्चों के सामने ही कुसुम को डंडे से पीटा। गंभीर रूप से घायल कुसुम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएचओ अंजू मिश्र ने हत्यारोपी पति नक्छेद को गिरफ्तार किया था। सीजेएम नवनीत सिंह के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी नक्छेद ने बताया था कि वह भोले बाबा का भक्त है और उसने माथे पर नाग का टैटू बनवा रखा है। उसने यह भी दावा किया था कि घटना वाले दिन उसने अधिक मात्रा में भांग का सेवन किया था, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसने यह कदम उठाया था।

नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज... इन 5 सेक्टरों में 46 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री-पजेशन का रास्ता साफ, पाबंदी हटी

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों खरीदारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में सेक्टर- 150 समेत पांच सेक्टरों की परियोजनाओं के नक्शे पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। करीब दो साल से ज्यादा समय से इन परियोजनाओं पर रोक लगी हुई थी, जिसे निर्माण कार्य और रजिस्ट्री दोनों प्रभावित हो रहे थे। अब इस फैसले के बाद न केवल रुके हुए कामों में तेजी आएगी बल्कि लोगों को अपने घर का मालिक बनने का रास्ता भी साफ हो गया है।

इस फैसले के तहत सेक्टर- 78, 79, 101, 150 और 152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को राहत मिली है। इन सभी सेक्टर में कई ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके हुए थे। अब संशोधित नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा और जहां काम पूरा हो चुका है वहां रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

बताया जा रहा है कि फैसले से करीब 35 हजार फ्लैट खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कई साल पहले अपने फ्लेट बुक किए थे। लेकिन अब तक उन्हें ना तो पजेशन मिला और ना ही उनके फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाई। अब नक्शे की मंजूरी के बाद इन खरीदारों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है और जल्द ही उन्हें अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। स्पोर्ट सिटी से जुड़ी करीब 46 ग्रुप हाउसिंग योजनाएं इस फैसले से प्रभावित हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट में निर्माण कहानी अधूरा पड़ा था। जबकि, कुछ में निर्माण पूरा होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। अब इन परियोजनाओं को दोबारा गति मिलेगी और निर्माण कार्य के साथ-साथ अन्य जरूरी प्रक्रियाएं भी तेजी से पूरी की जाएंगी।

बिल्डरों पर भी बकाया प्राधिकरण सख्त

इस पूरे मामले में एक बड़ी समस्या बिल्डरों पर बकाया राशि की भी रही है। जानकारी के मुताबिक, स्पोर्ट सिटी से जुड़े विंडो पर करीब 9318 करोड रुपए का बकाया है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि निर्माण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया के साथ-साथ बकाया वसूली पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। बिल्डरों को अपने बकाया भुगतान के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। इस मंजूरी के बाद अब उन परियोजनाओं में रजिस्ट्री शुरू हो सकेगी, जहां पहले कानूनी और तकनीकी अर्चना थी इससे हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और लंबे समय से रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा।

खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान

प्राधिकरण ने ये भी स्पष्ट किया है कि भारत सिटी परियोजना में खेल सुविधाओं को विकसित करना अनिवार्य होगा। बिल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल आवासीय निर्माण ही नहीं बल्कि खेल से जुड़ी सुविधाएं भी तय मानकों के अनुसार विकसित की जाएं। इसके लिए समय सीमा और शर्तें भी तय की गई है। बोर्ड बैठक में पुराने निर्णयो की समीक्षा करते हुए बदलाव किए गए हैं। नई नीति के तहत अक्षों की मंजूरी रजिस्ट्री और निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे परियोजनाओं को जल पूरा किया जा सकेगा। इससे न केवल खरीदार को राहत मिलेगी बल्कि प्राधिकरण को भी अपनी लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

नोएडा रियल एस्टेट को मिलेगा नया जीवन

इस फैसले को नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से अटकी परियोजनाओं के चलते बाजार में जो ठहराव आ गया था। अब उसमें सुधार आने की उम्मीद है। निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट में भी तेजी देखने को मिल सकती है। नोएडा प्राधिकरण का यह फैसला हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिन लोगों ने सालों पहले अपने सपनों का घर खरीदा था अब

घर में पालना चाहते हैं बिल्ली या कुत्ता, इससे पहले डिसाइड कर लें ये 5 बातें

घर में पालतू जानवर लेकर आना भले ही आपकी भावनाओं से जुड़ा फैसला हो, लेकिन ये बेहद जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करें। अगर आप भी अपने घर में को PET कुत्ता या बिल्ली पालना चाहते हैं तो इससे पहले ये 5 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।

लोग अपने घर में बिल्ली और कुत्ता ये दो ऐसे पेट्स हैं जो बहुत सारे लोग अपने घर में पालते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर पेट्स के साथ वीडियो और तस्वीरों को शेयर करने का भी काफी ट्रेंड है। इसके चलते भी कई लोग पेट्स पालने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि पेट्स के साथ खेलना और क्यूट फोटो क्लिक करवाने तक ही जर्नी सीमित नहीं होती है। यही वजह है कि पेट्स पेरेंट बनना हो तो यह आपके लिए सिर्फ इमोशन और प्यार भरा फैसला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार होना पड़ता है।

पेट्स को पालने के लिए आपको समय की जरूरत होती है, क्योंकि उनको खाना देने से लेकर साफ-सफाई और देखभाल तक की चीजें होती हैं। इसमें मेहनत भी लगती है और आपको समझदारी की जरूरत भी होती है। ऐसे में चाहे कुत्ता हो या फिर बिल्ली कोई भी जानवर घर लाने से पहले यह बहुत ही जरूरी चीज है कि आप उसकी देखभाल के लिए तैयार हो। यहां दी गई कुछ बातें जान लें।

समय की होती है जरूरत

पालतू जानवर ज्यादातर चीजों के लिए आपके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जैसे अगर आपने डॉग पालना है तो आपको उनको रोज सुबह और शाम बाहर ले जाना होता है। इसी तरह से बिल्लियों को भी आपका टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वो कुछ वक्त आपके साथ खेलना चाहती हैं। आप किसी भी तरह का छोटे जानवर यहां तक की मछलियां भी पालते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है समय से उनके लिए खाना देना और उनके रहने की जगह की सफाई करना। इसमें भी टाइम चाहिए होता है। ऐसे में अगर आप नौकरी पेशा हैं। अकेले रहते हैं तो पेट्स को पालना हेक्टिक हो सकता है और उनको भी परेशानी होती है

पैसे की भी होती है जरूरत

पालतू जानवर को घर में सिर्फ रखना या उनके साथ खेलना ही नहीं होता है, बल्कि उनके लिए सही खाना, टॉयज लेकर आने तक कई खर्च होते हैं। खासतौर पर रूटीन इंजेक्शन लगवाना, ग्रूमिंग और इसी के साथ बीमार होने पर डॉक्टर के यहां लेकर जाना तकये सारी चीजें कई बार काफी महंगी पड़ती हैं। खासतौर पर अगर आप किसी विदेशी नस्ल के पालतू जानवर को पाल रहे हैं तो ट्रेनिंग की जरूरत भी होती है और इसमें भी पैसे खर्च होते हैं।

घर में हो सही जगह

आप अपने घर में अगर कोई भी जानवर लेकर आ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि घर में उतनी जगह है या फिर नहीं। एक तो पेट्स को रहने के लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी होती है जैसे उनके सोने की जगह। इसके अलावा बिल्ली और डॉग ऐसे जानवर हैं जो काफी एक्टिव होते हैं और इधर-उधर दौड़कर खेलते हैं।

ये एक लंबे टाइम की है जिम्मेदारी

कई बार लोग शौक में या इंफ्लुएंस होकर पेट्स तो ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में परेशान हो जाते हैं। ऐसे में या तो लोग पेट्स को दूसरों को दे देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। इस तरह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पालतू जानवर को घर लाने से पहले ही ये समझ लें कि ये 1 दो दिन या कुछ महीनों की नहीं बल्कि लंबे टाइम की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान अगर आप समय, मेहनत और प्यार देने के लिए पूरी तरह से मेंटली तैयार हैं तो ही पेट्स लेकर आएं।

कैसी है आपकी एनर्जी?

कोई भी पालतू जानवर घर में लाने से पहले आपको ये भी समझना होगा कि आपकी एनर्जी कैसी है। जैसे अगर आप बहुत एक्टिव रहना पसंद करते हैं यानी सुबह जल्दी सोकर उठ सकते हैं। शाम को खाना खाने के बाद कुछ देर बाहर वॉक जरूर करते हैं तो आप डॉग को चुन सकते हैं। शांत स्वभाव के हैं तो आप इसके लिए कोई छोटा जानवर चुन सकते हैं जैसे बिल्ली पाल सकते हैं।

बॉडीकॉन ड्रेस के साथ इन 5 एक्सेसरीज को करें स्टाइल, सभी करेंगे आपके लुक की तारीफ

बॉडीकॉन ड्रेस एक ऐसी पोशाक है, जो शरीर को कसकर गले लगाती है और इसे पहनकर महिलाएं बेहद आकर्षक दिखती हैं। हालांकि, इस तरह की ड्रेस के साथ सही एक्सेसरीज पहनना बहुत जरूरी है, ताकि लुक और भी खास बन सके। सही एक्सेसरीज न केवल आपके लुक को पूरा करती हैं, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देती हैं। आज के फैशन टिप्स में जानिए इस तरह की ड्रेस पर कैसी एक्सेसरीज अच्छी लगती हैं।

हील वाली सैंडल का चयन करें

बॉडीकॉन ड्रेस के साथ ऊंची एड़ी यानि हील वाली सैंडल पहनना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। यह आपके पैरों को लंबा दिखा सकती हैं और आपको आत्मविश्वास से भरा महसूस करवा सकती हैं। काली, न्यूड या किसी हल्के रंग की हील सैंडल चुनें, जो आपकी ड्रेस के साथ मेल खाए। अगर आप लंबे समय तक हील वाली सैंडल पहनने में असहज महसूस करती हैं तो चौड़ी एड़ी वाली सैंडल या छोटी हील वाले विकल्प को चुन लें।

छोटे इयररिंग पहनें

बॉडीकॉन ड्रेस के साथ छोटे इयररिंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपके चेहरे को फ्रेम करते हैं और आपके लुक को कोमल और आकर्षक बनाते हैं। मोती वाले या गोल्डन रंग के छोटे कान के इयररिंग चुनें, जो आपकी ड्रेस के साथ अच्छे से मेल खाते हों। अगर आपकी ड्रेस में ज्यादा कढ़ाई या डिजाइन है तो गोल्डन हूप्स ही पहनें, ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और संतुलित दिखे।

छोटे बैग का उपयोग करें

छोटा बैग बॉडीकॉन ड्रेस के साथ एक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यह ड्रेस पर आकर्षण बना रहने देता है। यह न केवल आपकी चीजों को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाता है। छोटे बैग में फोन, पर्स, पैसे और मेकअप उत्पाद जैसे छोटे-मोटे सामान आसानी से समा सकते हैं। रंगों की बात करें तो काले, सुनहरे या हल्के रंग के बैग चुनें, जो आपकी ड्रेस के साथ मेल खाएं।

कमर पर बेल्ट लगाएं

इन दिनों बॉडीकॉन ड्रेस के साथ स्टाइलिश बेल्ट पहनने का काफी चलन है, जिसे आपको भी अपनाना चाहिए। इससे आपकी कमर का आकार उभरकर आएगा, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। बेल्ट चुनते समय उसकी चौड़ाई और डिजाइन पर ध्यान दें, ताकि वह आपकी ड्रेस के साथ मेल खाए। आप ड्रेस के ऊपर गोल्डन रंग की चेन वाली बेल्ट लगा सकती हैं, जो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं।

हाथों में चंकी कड़े पहनें

बॉडीकॉन ड्रेस के साथ हाथों में भी कुछ पहनना बनता है। आप इस लुक को और भी खास बनाने के लिए कलाई को चंकी कड़ों से सजा सकती हैं। ये बड़े आकार वाले कड़े होते हैं, जो हाथों को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। आपको गोल्डन या फिर ड्रेस के रंग से मेल खाते हुए चंकी कड़े पहनने चाहिए। ज्यादा खूबसूरत लुक के लिए अलग-अलग डिजाइन और आकार वाले कड़ों को एक साथ पहनकर देखें।

खूबसूरत वादियां, नदियां, झरने...लद्दाख के छोर पर बसा आखिरी गांव 'तुरतुक'

भारत में न सिर्फ सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, बल्कि हमारे यहां का नेचुरल ब्यूटी को भी शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। कई ऐसी अनजानी और अनछुई जगहें हैं जहां पर जाना आपके के लिए भी जन्नत में पहुंचने से कम नहीं होगा। कई बार तो प्रकृति के अजूबे हमें हैरान कर जाते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे लेह के आखिरी छोर पर बसे गांव तुरतुक के बारे में।

भारत में ही कई ऐसी छुपी हुई जगहें हैं जिनकी खूबसूरती और खासियत के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. नेचुरल ब्यूटी की बात हो तो लोगों को नदियां, पहाड़, झरने, झीलें ही याद आते हैं. मैदानों में गर्मी का मौसम काफी परेशान कर देने वाला होता है. ऐसे में अगर ठंडक और सुकून भरे माहौल में वक्त बिताना हो तो लोग सीधे पहाड़ों की ओर रुख करते हैं. इसी वजह से शिमला, मसूरी, कश्मीर जैसी जगहों पर जबरदस्त टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिलती है. फिलहाल ये सारे पॉपुलर प्लेस हैं, इसलिए आज एक खूबसूरत गांव के बारे में बात करेंगे, जहां आना आपके लिए लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक होगा. यहां पर आपको टूरिस्ट्स की भीड़ भी कम मिलेगी. इस गांव का नाम है 'तुरतुक'. ये भारत-पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब में पड़ता है और इसलिए इसे देश का आखिरी गांव भी मानते हैं.

लेह के आखिरी छोर पर बसा गांव तुरतुक अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना ही जाता है। यहां की संस्कृति के बारे में जानना भी आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। ये गांव ऐतिहासिक नजरिए से भी खास है।प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही शांत वातावरण इस गांव को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। ये गांव नेचर लवर और देश की संस्कृति, इतिहास को जानने वालों के लिए बेहद खास है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे पहुचें यहां और क्या है खासियत।

तुरतुक का इतिहास

लद्दाख के छोर पर बसा भारत का आखिरी गांव कहे जाने वाले तुरतुक का इतिहास भी बेहद खास है। ये गांव 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से निकलकर भारत का हिस्सा बना है। सीमा से इस गांव की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर पड़ती है। यहां पर रहने वाले लोग बाल्टी संस्कृति को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है यहां की भाषा और रहन-सहन के तरीकों में भी आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल के साथ।

कैसे पहुंच सकते हैं तुरतुक गांव?

अगर आपको तुरतुक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको लद्दाख के लेह पहुंचना होगा। सबसे जरूरी बात ये है कि आपको यहां सीधे एंट्री नहीं मिलती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है।दरअसल से सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होता है। सीमा से बेहद करीब होने की वजह से इस गांव में एंट्री करने वाले पर्यटकों की जांच भी की जाती है।

प्राकृतिक नजारे देख दिल हो जाएगा खुश

तुरतुक गांव सीमा क्षेत्र की वजह से तो खास माना ही जाता है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता देख आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वहीं संस्कृति का अनोखा संगम देखना भी एक बिल्कुल नया अनुभव होगा। अगर आप शहर के काम और भीड़भाड़ से थक चुके हैं और एक सुकून भरा ब्रेक चाहते हैं तो यहां आना ही चाहिए। यहां की खूबसूरती को आप शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। यहां पर एक खूबसूरत वाटर फॉल है जिसे तुरतुक झरना के नाम से भी जानते हैं।

म्यूजियम करें विजिट

आप तुरतुक जाएं तो यहां पर बने बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम को भी विजिट करना चाहिए। ये पत्थरों और लकड़ी से बने घर हैं जिनमें आपको बाल्टी संस्कृति से जुड़ी चीजें जैसे वेशभूषा, पुराने बर्तिन आदि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1971 के युद्ध के इतिहास की भी झलक देखने को मिल जाएगी।

ये जगहें भी करें एक्सप्लोर

नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो आपको खुबानी के बाग (Apricot Farms) जरूर देखने चाहिए। अप्रैल मंथ में एप्रिकॉट ब्लॉसम देखना आपके लिए खूबसूरत सपने में पहुंच जाने जैसा होगा। इसके अलावा आप पोलो ग्राउंड जा सकता है। नेचुरल कोल्ड स्टोरेज प्रणाली के बारे में जानकारी ले सकते हैं और शाही घर देख सकते हैं जो यहां के इतिहास की विरासत है।

बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों का सुनहरा अवसर, 1000 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाला संस्थान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती के तहत कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में वैकेंसी निर्धारित की गई है। सबसे ज्यादा 200 पद उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि गुजरात में 125 और पंजाब में 100 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 80-80, तमिलनाडु में 65, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 60-60 पद, असम में 50, तेलंगाना में 30, पश्चिम बंगाल में 30, हिमाचल प्रदेश में 20, अरुणाचल प्रदेश में 15, झारखंड और केरल में 10-10 और नागालैंड में 5 पद शामिल हैं।

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा। इस पद पर नियुक्ति मिलने के बाद उम्मीदवारों को 48,480 रुपए से लेकर 85,920 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपए के साथ लागू टैक्स और पेमेंट गेटवे शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपए रखा गया है, जिस पर अतिरिक्त टैक्स और चार्ज लागू होंगे।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

यह भर्ती उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है, जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

बैंक खाते से अब नहीं उड़ेंगे पैसे, ओटीपी चुराने वालों के लिए आ गई नई तकनी, हैकर्स के भी उड़ जाएंगे होश

तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अब एक बेहद हाईटेक तकनीक पर काम चल रहा है। बैंक और टेलीकॉम कंपनियां मिलकर जल्द ही 'साइलेंट ऑथेंटिकेशन' नाम का एक नया सिस्टम लाने वाली हैं, जिसके बाद ओटीपी चोरी होने पर भी जालसाज आपके बैंक खाते में सेंध नहीं लगा पाएंगे। यह नई तकनीक मौजूदा वन-टाइम पासवर्ड का एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बनने जा रही है। फिलहाल यह सिस्टम टेस्टिंग फेज में है और इसके पूरी तरह लागू होते ही साइबर क्रिमिनल्स के सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे, क्योंकि बैंक किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पलक झपकते ही ब्लॉक कर देंगे।

क्या है साइलेंट ऑथेंटिकेशन?

इस नई और आधुनिक तकनीक को बैंकिंग सेक्टर के लिए एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन का नाम दिया जा रहा है। मौजूदा समय में ऑनलाइन पेमेंट या किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए यूजर्स को पासवर्ड के साथ-साथ अपने मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को वेरिफाई करना होता है। ऐसे में जालसाज सिम स्वैप या कॉल फॉरवर्डिंग जैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट आसानी से खाली कर रहे हैं। अगर किसी हैकर के पास आपके कार्ड की डिटेल और मोबाइल नंबर का एक्सेस पहुंच जाता है, तो वह पल भर में आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा लेता है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के फ्रॉड के ढेरों मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा है। इसी बड़े खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए बैंक और टेलीकॉम कंपनियां इस नए समाधान पर काम कर रही हैं।

बैकग्राउंड में कैसे काम करेगा यह स्मार्ट सिस्टम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइलेंट ऑथेंटिकेशन तकनीक पूरी तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर आधारित होगी। इसमें स्क्रीन पर हैकर्स को भनक तक नहीं लगेगी कि बैंक उनके ट्रांजैक्शन पर गुप्त रूप से नजर रख रहा है। इस सिस्टम में असली यूजर की पहचान करने के लिए बैंक अकाउंट और ओटीपी के साथ-साथ मोबाइल डिवाइस की आईडी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही बैंक खाते से कोई ट्रांजैक्शन शुरू होगा, बैंक रियल टाइम में यह वेरिफाई कर लेगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला असली डिवाइस एक्टिव स्टेटस में है या नहीं।

टेलीकॉम ऑपरेटर देंगे डिवाइस की सटीक जानकारी

ट्रांजैक्शन के वक्त डिवाइस के एक्टिव स्टेटस की यह सटीक जानकारी टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए सीधे बैंक तक पहुंच जाएगी। इस तरह से बैंक को तुरंत पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है वह असली ग्राहक है या कोई हैकर किसी अन्य डिवाइस के माध्यम से इसे अंजाम दे रहा है। अगर ट्रांजैक्शन के वक्त असली डिवाइस एक्टिव नहीं मिलता है, तो बैंक तुरंत उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देगा और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से भी पिछले काफी समय से इस खास तकनीक पर काम किया जा रहा है।

ईरान संघर्ष का असर, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ीं

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान संघर्ष का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन, उर्वरक, माल ढुलाई और विदेशी मुद्रा जैसे अहम क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है।

भले ही बांग्लादेश इस संघर्ष क्षेत्र से भौगोलिक रूप से दूर है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहरे जुड़ाव के कारण इसका असर तेजी से महसूस हो रहा है।

इस व्यवधान का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और एलएनजी गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग और उर्वरक की उपलब्धता को प्रभावित करती है, जो कृषि के लिए बेहद जरूरी हैं।

वैश्विक बाजार में इसका असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है, एलएनजी की आपूर्ति में देरी हो रही है और माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। उर्वरकों की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है, जिससे खाद्य उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है।

बांग्लादेश के लिए ये सभी झटके एक साथ आ रहे हैं। ऊर्जा की बढ़ती लागत बिजली और परिवहन की कीमतों को ऊपर ले जा रही है, जबकि महंगे उर्वरक कृषि लागत को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही माल ढुलाई महंगी होने से आयात लागत में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समस्या सिर्फ कीमतों में वृद्धि की नहीं है, बल्कि इन जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता भी चिंता का विषय बनती जा रही है। ईंधन, उर्वरक या शिपिंग में किसी भी तरह की कमी अर्थव्यवस्था को कीमतों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आयात महंगा हो रहा है, इससे निर्यात और प्रवासी आय (रिमिटेंस) पर भी दबाव पड़ सकता है, खासकर अगर खाड़ी देशों के श्रम बाजार कमजोर होते हैं।

सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है। वैश्विक ईंधन कीमतों का पूरा असर जनता तक न पहुंचे, इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। वहीं, कमजोर कर संग्रह के कारण अतिरिक्त राहत देने की गुंजाइश सीमित हो गई है।

ऊर्जा और उर्वरक की बढ़ती लागत का असर परिवहन और खाद्य कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे स्कॉस्ट-पुश महंगाई की स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति में केवल मौद्रिक नीति से महंगाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और सरकार को महंगाई तथा आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है। यदि आर्थिक गतिविधियां धीमी होती हैं तो पहले से कमजोर बैंकिंग व्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

फजीहत के बाद बदले पाकिस्तान के सुर: यूएस -ईरान समझौते पर अब किया टिप्पणी से इनकार

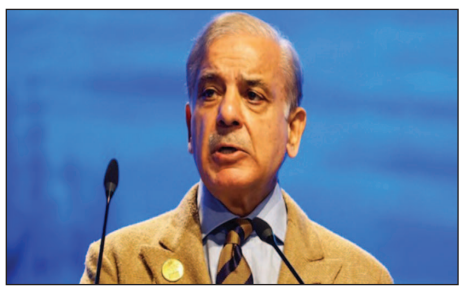

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने सोमवार को ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति प्रस्ताव की खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, विदेश कार्यालय ने कहा कि शांति प्रक्रिया जारी है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, ₹45 दिवसीय युद्धविराम की पेशकश या 15-सूत्रीय समझौते की कई खबरें आई हैं। हम इन पर टिप्पणी नहीं करते हैं।₹

पाकिस्तान का यह बयान रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान और अमेरिका को पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई एक योजना मिली है, जो युद्धविराम करा सकती है। रिपोर्ट में एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि युद्धविराम की यह रूपरेखा रातोंरात दोनों पक्षों के साथ साझा की गई थी।

अमेरिकी रिपोर्ट में मध्यस्थता का दावा

अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने अपनी एक रिपोर्ट में स्रोतों का हवाला देते हुए बताया था कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थ एक संभावित 45-दिवसीय युद्धविराम पर चर्चा कर रहे थे। जो युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने की दिशा में दो-चरणीय समझौते का हिस्सा हो सकता है। इसमें पहले युद्धविराम और फिर व्यापक समझौता किए जाने का दावा किया गया था।

ईरान ने खारिज किया प्रस्ताव

ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जवाब देते हुए तेहरान ने युद्धविराम को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि युद्ध का स्थायी अंत जरूरी है। ईरान के जवाब में 10 सूत्र शामिल थे, जिनमें क्षेत्र में संघर्षों की समाप्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन के लिए एक प्रोटोकॉल, प्रतिबंधों को हटाना और पुनर्निर्माण शामिल थे।

पाकिस्तानी प्रस्ताव खारिज होने की क्या थी वजह?

मध्यस्थ बन रहे पाकिस्तान के युद्धविराम प्रस्ताव के जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत अल्टीमेटम और युद्ध अपराधों के अंजाम देने की धमकी के साथ असंगत है। प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि 15-सूत्रीय योजना जैसी पिछली अमेरिकी मांगों को बहुत ज्यादा होने की वजह से अस्वीकार कर दिया गया था।

पाकिस्तान की भूमिका

पाकिस्तान खुद को शांति प्रक्रिया में एक सूत्रधार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों और ईरान के साथ अपने कामकाजी संबंधों का लाभ उठा रहा है।

ट्रंप की ईरान को चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर एक निश्चित समयसीमा के भीतर युद्धविराम नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से नहीं खोला तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा।

अंडमान-निकोबार में पुलिस को सफलता : पकड़े गए म्यांमार के 11 शिकारी, तीन दिनों के अभियान के बाद मिली कामयाबी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दूरस्थ स्थान से कुल 11 म्यांमार के शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह गिरफ्तारी का अभियान 4 अप्रैल से शुरू हुए था। उन्होंने बताया कि 'सी सेंटिनल' अभियान के दौरान निकोबार जिले के नानकोवरी द्वीप से शिकारियों को पकड़ा गया। डीजीपी हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने पीटीआई को बताया, 'पुलिस ने काकाना, पिलपिलो, पोंधा और डेरिंग के समुद्री क्षेत्रों में 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे से अवैध शिकार विरोधी अभियान शुरू किया गया था।'

दरअसल, अभियान के दौरान, उत्तरी काकाना के तट के पास एक संदिग्ध म्यांमार की अवैध शिकार करने वाली नौका का पता चला। उन्होंने बताया, "गिरफ्तारी से बचने के लिए शिकारियों ने अपनी नाव की लंगर की रस्सी काट दी और तिलोंग चाउंग के पास दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर भागने की कोशिश की। पुलिस दल ने नाव का पीछा किया और भारतीय तटरक्षक बल के समन्वय से उसे रोकने का प्रयास किया। हमारे एक अधिकारी ने चेतावनी के तौर पर दो राउंड फायरिंग की। हालांकि, शिकारियों ने चेतावनी को अनसुना कर भागना जारी रखा।"

11 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने अंत में उस पोत को रोक लिया, जिसे आइल ऑफ मैन द्वीप के पास छोड़ दिया गया था, जहां से शिकारी घने जंगलों में भाग गए। डीजीपी ने बताया, '5 अप्रैल को पुलिस और सेना के जवानों की एक संयुक्त टीम ने संक्षिप्त पीछा करने के बाद एक म्यांमार नागरिक को पकड़ा। 6 अप्रैल को जंगल में छिपे हुए 10 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर, इस अभियान के दौरान 11 विदेशी शिकारियों को पकड़ा गया।' उन्होंने बताया कि अवैध रूप से काटी गई लगभग 800 किलोग्राम समुद्री खीरा भी बरामद की गई।

कोमा में है मोजतबा खामेनेई, ईरान के इस शहर में चल रहा सर्वोच्च नेता का इलाज ; रिपोर्ट में बड़ा दावा

लंदन, एजेंसी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोजतबा खामेनेई वर्तमान में कोम शहर में इलाज करवा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई अचेत अवस्था में हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मोजतबा किसी भी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं।

'द टाइम्स यूके' की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कूटनीतिक मेमो अमेरिकी और इस्राइली खुफिया एजेंसियों द्वारा खाड़ी सहयोगियों के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित है। इस रिपोर्ट में पहली बार सर्वोच्च नेता के ठिकाने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा खामेनेई का कोम शहर में इलाज चल रहा है और इस वजह से वे शासन के किसी भी निर्णय में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

मोजतबा की सार्वजनिक अनुपस्थिति ने गहराया शक

पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद से मोतबा खामेनेई ने कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। उनके नाम से जारी किए गए संदेशों का प्रसारण ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। इसकी वजह से मोजतबा के गंभीर रूप से घायल होने की खबरों को और बल मिला है।

अमेरिकी रिपोर्टों में अलग-अलग दावे

ईरानी अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि देश की कमान नए सर्वोच्च नेता के हाथ में है। इसके बावजूद कई अमेरिकी रिपोर्टों में खामेनेई की सेहत पर सवाल खड़े किए हैं। किसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोजतबा कोमा में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं, द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमलों में खामेनेई ने एक हाथ और एक पैर खो दिया है।

ट्रंप ने दी तबाही मचाने की चेतावनी

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार आठ बजे (ईस्टर्न टाइम) तक एक समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इस समय सीमा के बाद कोई पुल और कोई बिजली संयंत्र नहीं बचेगा। ट्रंप ने स्वीकार किया कि संघर्ष 28 फरवरी को शुरू होने पर ईरान बहुत शक्तिशाली स्थिति में था, लेकिन अब अमेरिका ने उसके सिर को काट दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम 47 साल पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह ठीक चल रहा है, लेकिन हमें देखना होगा। आपको यह समझना होगा, हम इन लोगों के साथ 47 साल से निपट रहे हैं।'

'अमेरिका चांद की सतह पर जल्द लौटेगा!' आर्टेमिस-2 के चार अंतरिक्ष यात्रियों से और क्या बोले ट्रंप?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टेमिस II मिशन के क्रू सदस्यों से बात की और अंतरिक्ष में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस मिशन से चंद्रमा पर अमेरिका की वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अंततः चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करेगा और फिर मंगल ग्रह की ओर बढ़ेगा।

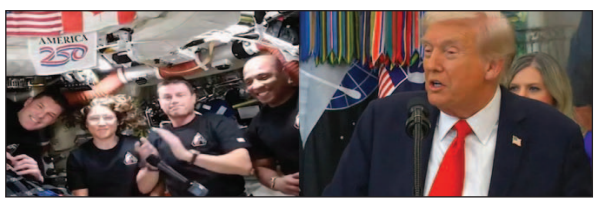

अंतरिक्ष यात्रा में नया कीर्तिमान

यह बात उन्होंने तब कही जब मिशन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान में सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड तोड़ा। ट्रंप ने कहा 'आज आपने इतिहास रचा है और पूरे अमेरिका को अविश्वसनीय रूप से गौरवान्वित किया है।' उन्होंने कहा कि मानव अंतरिक्ष यान में जो कुछ वे कर रहे हैं, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यह वास्तव में विशेष है। आप सभी ने इस दिन को संभव बनाया है। आपने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है।

अमेरिका की अंतरिक्ष में वापसी

ट्रंप ने कहा कि चंद्रमा की यात्रा अधिक सामान्य हो जाएगी और उन्होंने मंगल ग्रह की भविष्य की यात्रा का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा 'आखिरकार, अमेरिका वापस आ गया है और अमेरिका कई मायनों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आया है। हम दुनिया में सबसे आगे हैं। आर्टेमिस क्रू ने नासा द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट में उड़ान भरी, ढाई लाख मील से अधिक की यात्रा की और महान अपोलो 13 द्वारा निर्धारित दूरी का रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका एक सीमावर्ती राष्ट्र है और आर्टेमिस 2 के चार बहादुर अंतरिक्ष यात्री आधुनिक युग के अग्रणी हैं।' राष्ट्रपति ने आगे कहा 'हम एक बार फिर अपना झंडा फहराएंगे और इस बार हम सिर्फ पदचिह्न नहीं छोड़ेंगे। हम चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करेंगे और हम मंगल की ओर बढ़ेंगे। यह बहुत रोमांचक होगा। अमेरिका अंतरिक्ष में और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें किसी से पीछे नहीं रहेगा और हम सितारों की ओर नेतृत्व करना जारी रखेंगे।'

कब होनी है पृथ्वी पर वापसी?

यह मिशन न केवल रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, बल्कि चांद के उस हिस्से को देखने का भी मौका देगा, जिसे इंसान पहले कभी इतनी करीब से नहीं देख पाए। करीब 10 दिन के इस मिशन के बाद 10 अप्रैल को अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में उतरकर पृथ्वी पर लौटेगा। नासा का यह मिशन भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। नासा ने बताया कि इस कदम को लेकर एजेंसी का लक्ष्य है कि 2028 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास इंसानों की लैंडिंग कराई जाए।

कौन-कौन से अंतरिक्ष यात्री इसमें गए है?

गौरतलब है कि नासा के आर्टेमिस II मिशन में चार अनुभवी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन हैं, जबकि पायलट की जिम्मेदारी विक्टर ग्लोवर के पास है। इतना ही नहीं मिशन में दो स्पेशलिस्ट भी हैं, क्रिस्टिना कॉच और कनाडाई स्पेस एजेंसी के जेरमी हैन्सन। ये चारों अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्षयान में सवार हैं और चाँद के सबसे नजदीकी मार्ग पर 10-दिन की रोमांचक यात्रा पर हैं। मिशन का उद्देश्य न केवल चाँद के पास से गुजरना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष यात्रा के नए रिकॉर्ड भी स्थापित करना है।

सीएम हिमंत मास्टरस्ट्रोक बाबू आसोनी योजना के तहत अब मेल स्टूडेंट्स को भी मिलेगी आर्थिक मदद

नई दिल्ली, एजेंसी। असम सरकार ने उच्च शिक्षा में पढ़ रहे पुरुष छात्रों को आर्थिक संबल देने के लिए नई वित्तीय सहायता योजना 'बाबू असोनी' शुरू किए जाने का ऐलान किया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह योजना 01 फरवरी से लागू होगी। ऐसे में जो भी पात्र छात्र होंगे, हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पुरुष स्टूडेंट्स से किया गया एक पुराना वादा पूरा करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दबाव को कम करने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना है।

कितनी मिलेगी सहायता

इस योजना के तहत यूजी पाठ्यक्रमों में नामांकित पुरुष छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए, वहीं परास्नातक स्टूडेंट्स को 2,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी।

जानिए कौन होगा पात्र

प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम है। वह स्टूडेंट्स इस योजना के पात्र होंगे। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के पुत्र या जिन परिवारों की आय 4 लाख रुपए से ज्यादा है, वह छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

क्यों जरूर है योजना

बता दें कि लोकसभा में 2023-24 के दौरान पेश आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 15 से 29 साल आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 14.1% रही है। ऐसे में सरकार का मानना है कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में निवेश से रोजगार की संभावनाएं अधिक बेहतर होंगी।

योजनाओं का विस्तार

बाबू असोनी योजना राज्य सरकार की उन पहलों का विस्तार मानी जा रही है, जो अब तक मुख्य रूप से छात्राओं पर केंद्रित थी। 'निजुत मोइना' योजना के मध्याम से बालिकाओं को उच्च माध्यमिक से लेकर स्नानतकोत्तर तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिससे नामांकन बढ़ा है और बाल विवाह में भी कमी देखने को मिली है। असम सरकार का कहना है कि नई योजना से उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट रेट घटने के साथ छात्रों को फ्यूचर में रोजगार के मौकों के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

बंगाल एसआईआर में वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम बाहर, मालदा और मुर्शिदाबाद में भारी छंटनी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से संशोधित मतदाता सूची के मुताबिक कुल 90 लाख 83 हजार 345 नाम हटा दिए गए हैं। आयोग द्वारा जिलेवार सूची जारी करने के साथ ही अब मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है, यानी अब मतदान से पहले इसमें कोई नया नाम नहीं जोड़ा जा सकेगा।

आयोग के विश्लेषण के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे। 28 फरवरी को आई पहली सूची में ही करीब 63.66 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 60,06,675 नामों को विचाराणाधीन श्रेणी में रखा गया था।

कुल मतदाताओं की संख्या

सोमवार को इन नामों का निपटारा करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि इनमें से 27 लाख 16 हजार 393 लोग अयोग्य पाए गए, जबकि 32 लाख 68 हजार 119 को पात्र मानकर सूची में बहाल किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 6,77,20,728 रह गई है।

जिलों का हाल

मतदाता सूची के इस महा-शुद्धिकरण का सबसे व्यापक असर सीमावर्ती और घनी आबादी वाले जिलों में देखा गया है। सीमावर्ती जिले जैसे कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना उन जगहों में शामिल हैं, जहां वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं। मालदा में 8.28 लाख विचारणाधीन मामलों में से 5।88 लाख को अयोग्य ठहराया गया। मुर्शिदाबादजिले में कुल 7.48 लाख से अधिक नाम सूची से बाहर हुए हैं (पुराने और नए आंकड़े मिलाकर)। उत्तर 24 परगना में अब तक कुल 12.60 लाख से अधिक नामों पर कैंची चली है। उत्तर दिनाजपुर में 4.80 लाख मामलों में से 3.02 लाख लोग पात्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। वहीं कोलकाता में शहरी क्षेत्रों में प्रभाव कम रहा, दक्षिण कोलकाता से करीब 2.49 लाख और उत्तर कोलकाता से 4.47 लाख (कुल संचित) नाम हटे हैं।

दो चरणों में मतदान

पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा वहीं दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

किसी ने छठी तो किसी ने 12वीं क्लास में छोड़ी पढ़ाई, इन हसीनाओं ने नहीं देखा कॉलेज का मुंह

आज की इस खबर में हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन खूब सफलता हासिल की है।

हमारे समाज की एक सोच है कि अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़ता-लिखता नहीं है तो वह जिंदगी में कुछ नहीं करता है। हालांकि, अब समाज की यह सोच धीरे-धीरे बदलती जा रही है। इसके पीछे का कारण वो सितारे हैं, जो कम पढ़-लिखकर भी आज खूब नाम कमा रहे हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन खूब सफलता हासिल की है।

कंगना रनौत

कंगना रनौत को बॉलीवुड की 'क्वीन' और 'पंगा गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है। अभिनेत्री इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर चर्चा में चल रही हैं। बात करें कंगना की पढ़ाई की तो अभिनेत्री ने 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। इसके बाद अभिनेत्री दिल्ली आ गईं और मॉडलिंग में अपना करियर बनाया। कंगना नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजी गई हैं। आज वह एक सफल अभिनेत्री होने के साथ-साथ फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं।

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपना नाम बुलंद करने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बंगलूरू से अपनी पढ़ाई की है। शिक्षा पूरी करने के लिए अभिनेत्री ने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने अपने करियर को तवज्जो दिया और मॉडलिंग करने लगीं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई।

आलिया भट्ट

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट नेशनल अवॉर्ड विनर भी हैं। हर कोई उनके अभिनय की प्रशंसा करता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो अभिनेत्री की आलोचना भी की जाती है। ट्रोल्स को लगता है कि कम पढ़े-लिखे होने की वजह से आलिया को कई चीजों की नॉलेज नहीं है। बता दें कि आलिया ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और फिर बॉलीवुड में एंट्री कर ली थी।

करिश्मा कपूर

अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख लिया था। उस समय अभिनेत्री केवल 16 साल की थीं। फिल्मों में आने की वजह से उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बता दें कि करिश्मा ने केवल छठी क्लास तक ही पढ़ाई की है।

रश्मिका मंदाना के बर्थडे पर विजय देवरकोंडा ने शेयर की राणाबाली की अनसीन वीडियो, दिखा जयाम्मा का प्यारा लुक

रश्मिका मंदाना के शादी के बाद उनका यह पहला 30 वां जन्मदिन है। इसलिए उनके स्टार पति ने उनके इस खास दिन को और भी खास बनाया है। एक्टर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट राणाबली का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया और उसे एक खास और मिनिमल कैप्शन के साथ जोड़ा है।

विजय देवरगोंडा ने अपने इंस्टाग्राम पर राणाबली का बीटीएस वीडियो शेयर किया है। दिल को छू लेने वाला बीटीएस क्लिप एक नोट के साथ शुरू होता है, जिसमें लिखा है, ग्रे रंग में रंगी दुनिया में, वह उसकी एकमात्र रंग थी।

वीडियो में जयम्मा की पुरानी तस्वीरों की झलक दिखाई जाती है। इसके बाद सेट पर टीम रश्मिका का स्वागत करती है। क्लिप में वह क्रिएटिव टीम के साथ अपने किरदार जयम्मा पर चर्चा करती दिख रही हैं, जिसमें उनके लुक, स्टाइलिंग, पोज और उनकी परफॉर्मेंस के दूसरे पहलू शामिल हैं। जयम्मा का किरदार निभाते हुए, रश्मिका मुस्कुराती हुई और अपने रोल में पूरी तरह डूबी हुई दिख रही हैं।

वीडियो के आखिर में, विजय और रश्मिका एक हल्के-फुल्के पल शेयर करते हुए दिखाए गए हैं। वह घास की ढेर में एक साथ लेटे हुए, राणाबली पर अपने काम की एक मजेदार और कैंडिड सीन करते हुए नजर आते हैं। विजय ने इस खास बीटीएस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, आई लव यू जयम्मा। विजय के इस पोस्ट को रश्मिका ने रीपोस्ट किया है।

इसके अलावा मैसा के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर एक्ट्रेस को बर्थडे विश किया है। अनफॉर्मूला फिल्म्स ने एक्ट्रेस का एक ज़बरदस्त लुक दिखाते हुए लिखा है, उसने मोहनी रूप से राज किया। उसने दया से जीता। अब वह प्योर रेज के साथ आ रही है। पोस्टर में आगे लिखा था, टीम मैसा हमेशा स्टनिंग रश्मिका मंदाना को जबरदस्त हैप्पी बर्थडे विश करती है। इमेज में, रश्मिका गुस्से से घूरती हुई दिख रही हैं, उनके चेहरे पर चोट और खून के निशान हैं, जो उनके इंटेंस कैरेक्टर को दिखाता है।

राणाबली 2026 में आने वाली एक इंडियन पीरियड एक्शन ड्रामा है, जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना हैं, और इसे राहुल सांकृत्यायन ने डायरेक्ट किया है। ब्रिटिश राज (1854–1878) के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है, जो रायलसीमा की सच्ची और दबी हुई ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। राणाबली 11 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी।

इसके अलावा, रश्मिका तेलुगु पैन इंडियन पीरियड ड्रामा मैसा के लिए भी तैयारी कर रही हैं। रविंद्र पुले द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई एक्शन थ्रिलर फिल्म इसी साल रिलीज होगी। उनकी झोली में कॉकटेल-2 भी है, जो 19 जून 2026 को रिलीज होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com